

स्वस्थ धरा, खेत हरा

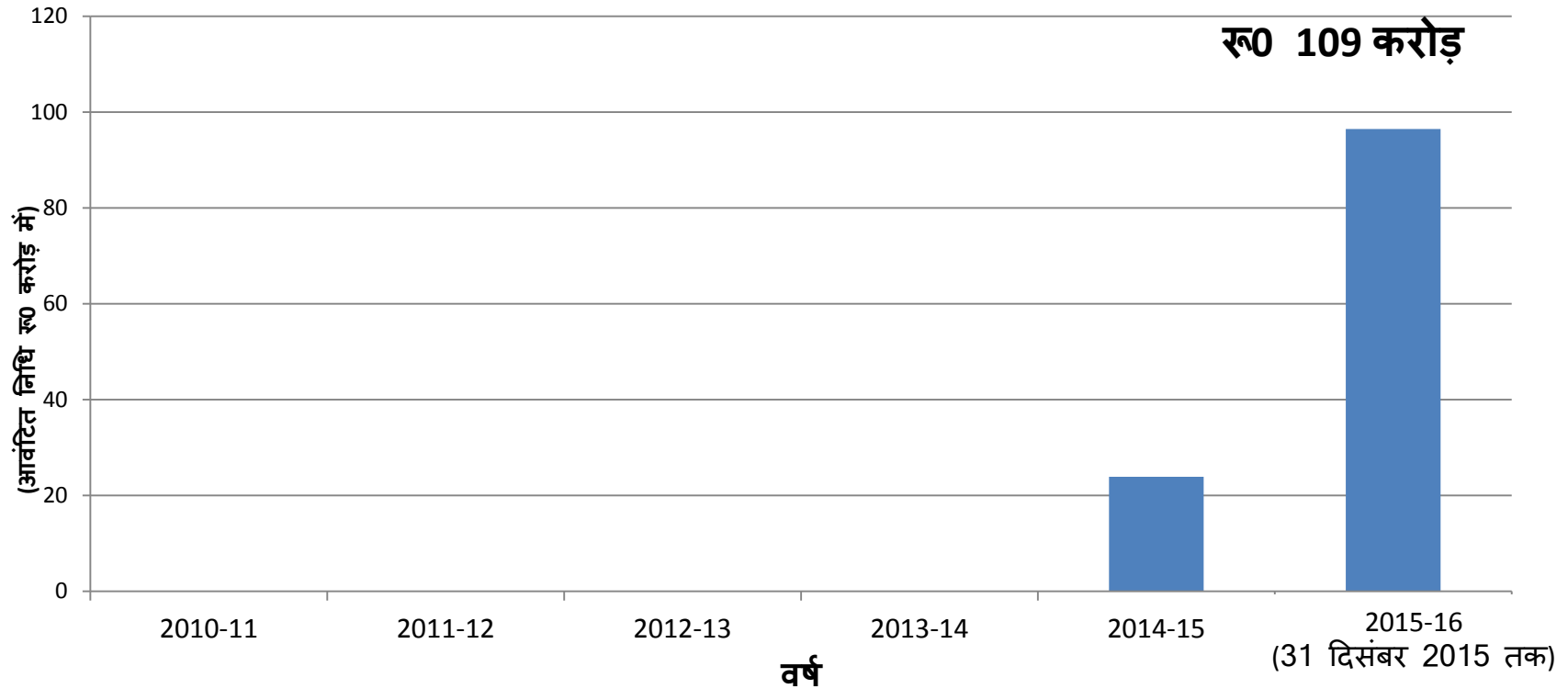


19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रत्येक किसानों के लिए नई स्कीम मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरू किया गया था।



स्वस्थ धरा, खेत हरा

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (वार्षिक आवंटन)



1. प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सभी 14 करोड़ भू-जोत धारियों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड ।
2. 31 दिसंबर, 2015 तक वर्ष 2015-16 में राज्यों को ₹0 109 करोड़ आवंटित किए ।
3. प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सभी 14 करोड़ भू-जोत धारियों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ₹0 568 करोड़ अनुमोदित किया गया ।



स्वस्थ धरा, खेत हरा

जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड

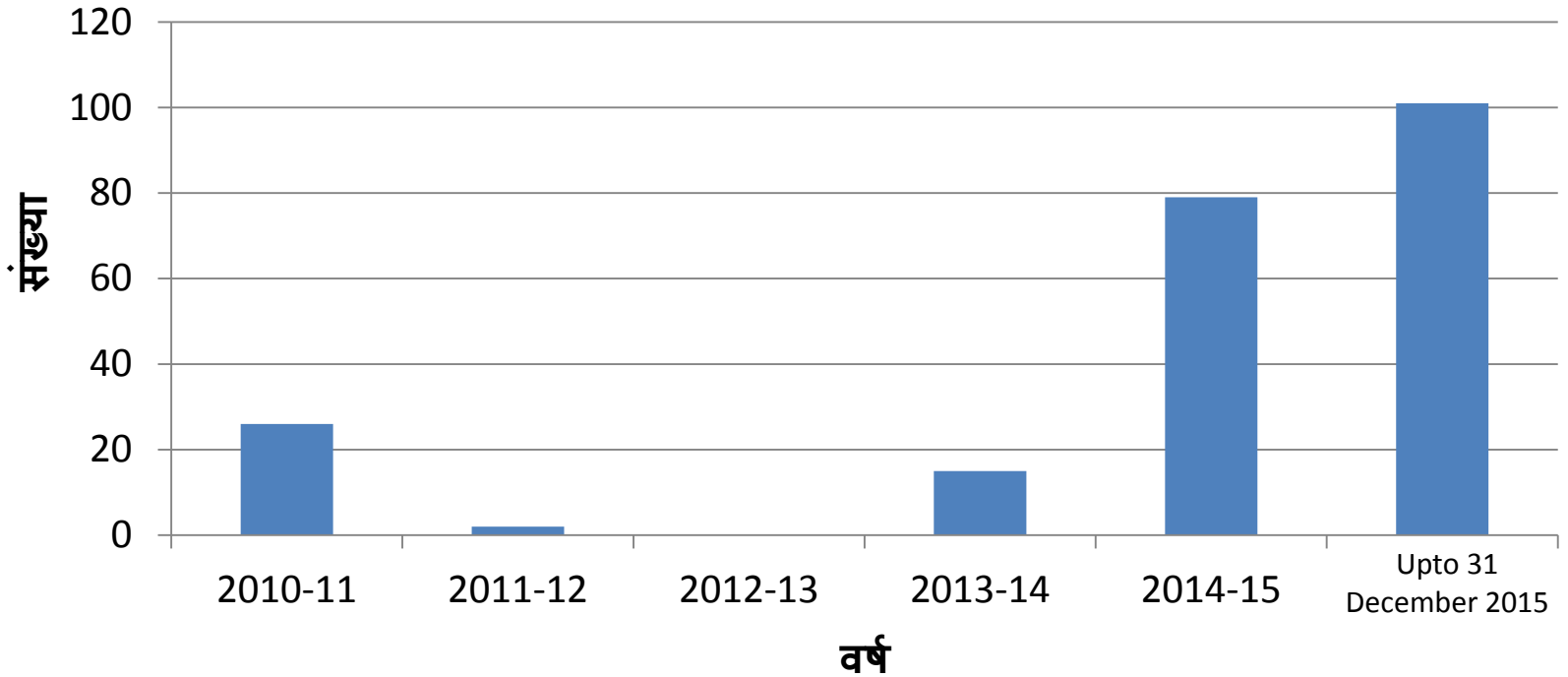


वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड लक्षित किए गए



स्वस्थ धरा, खेत हरा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

संस्वीकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

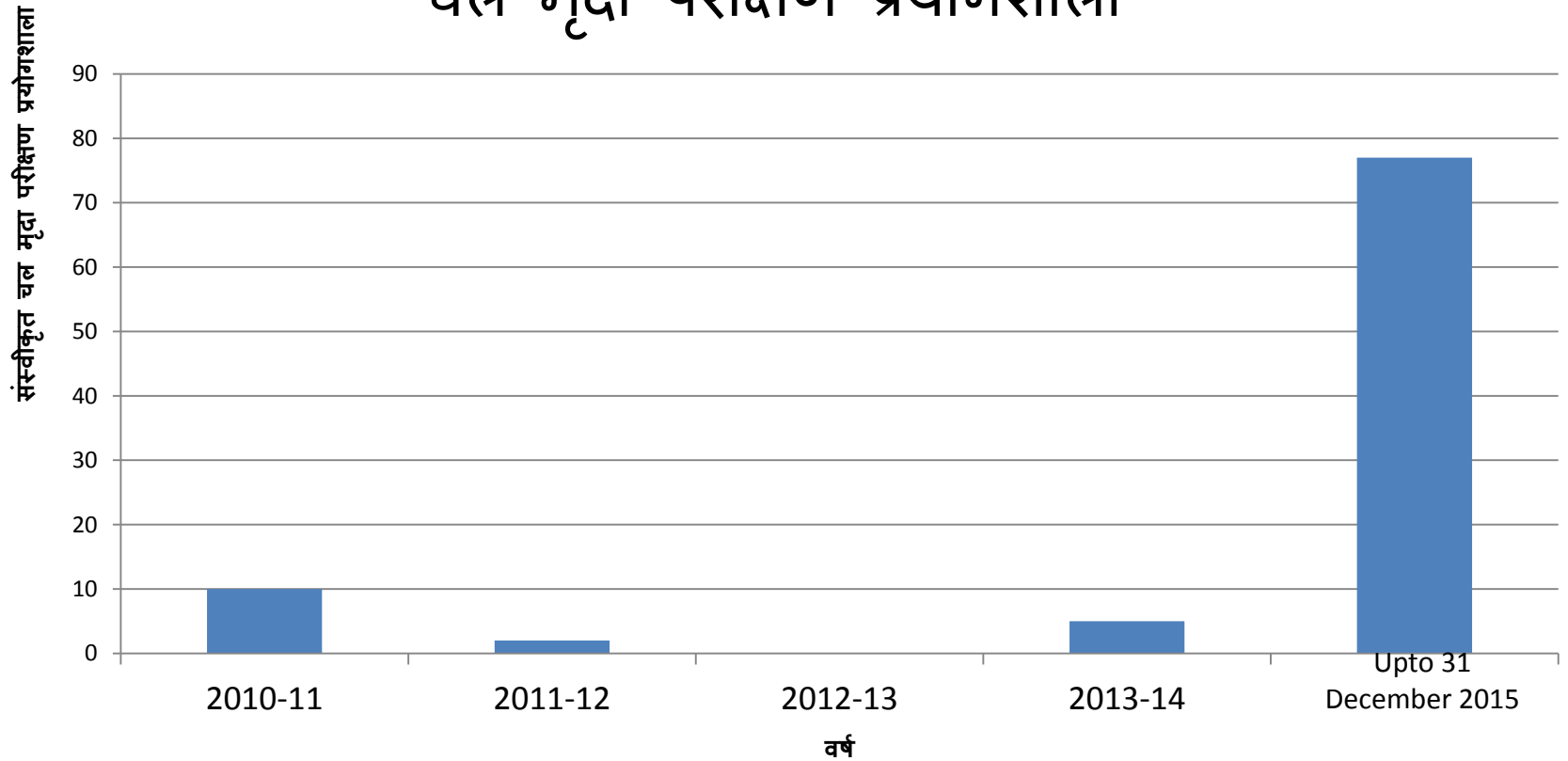


पिछले 4 वर्षों में 43 संस्वीकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की तुलना में वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 79 एवं 101 प्रयोगशालाएं संस्वीकृत किए गए।



स्वस्थ धरा, खेत हरा

स्वस्थ धरा, खेत हरा चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

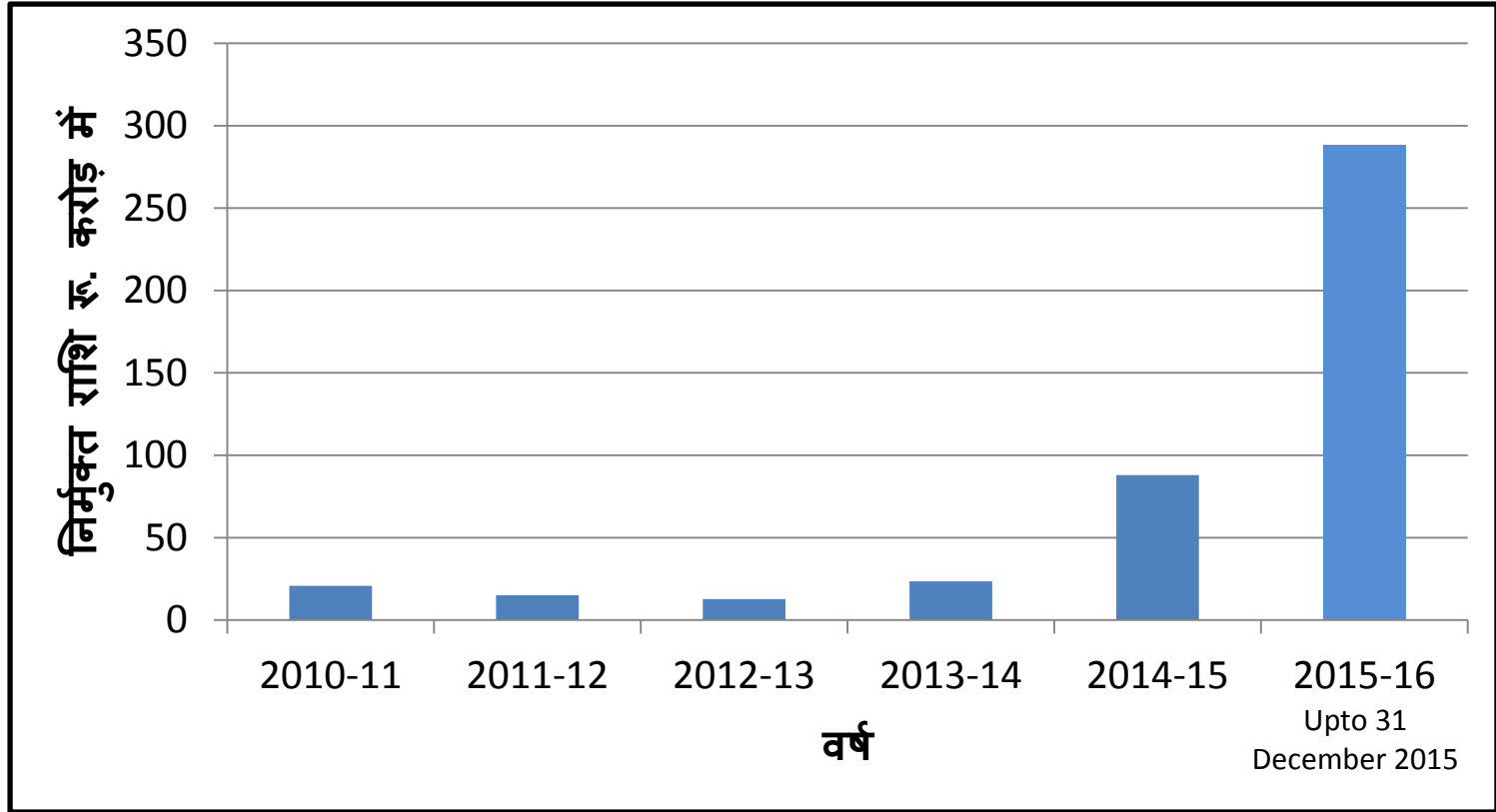


पिछले 4 वर्षों में 17 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के मुकाबले वर्ष 2014-15 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) 77 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं संस्वीकृत किए गए।



स्वस्थ धरा, खेत हरा

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राज्यों को निर्मुक्त राशि



वर्ष 2014-15 में 88 करोड़ रु. और 2015-16 में 288 करोड़ रु. की तुलना में 4 वर्षों में 72 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए। (179 करोड़ रु. पोकेवीवाई + 109 करोड़ रु. एसएचएम)



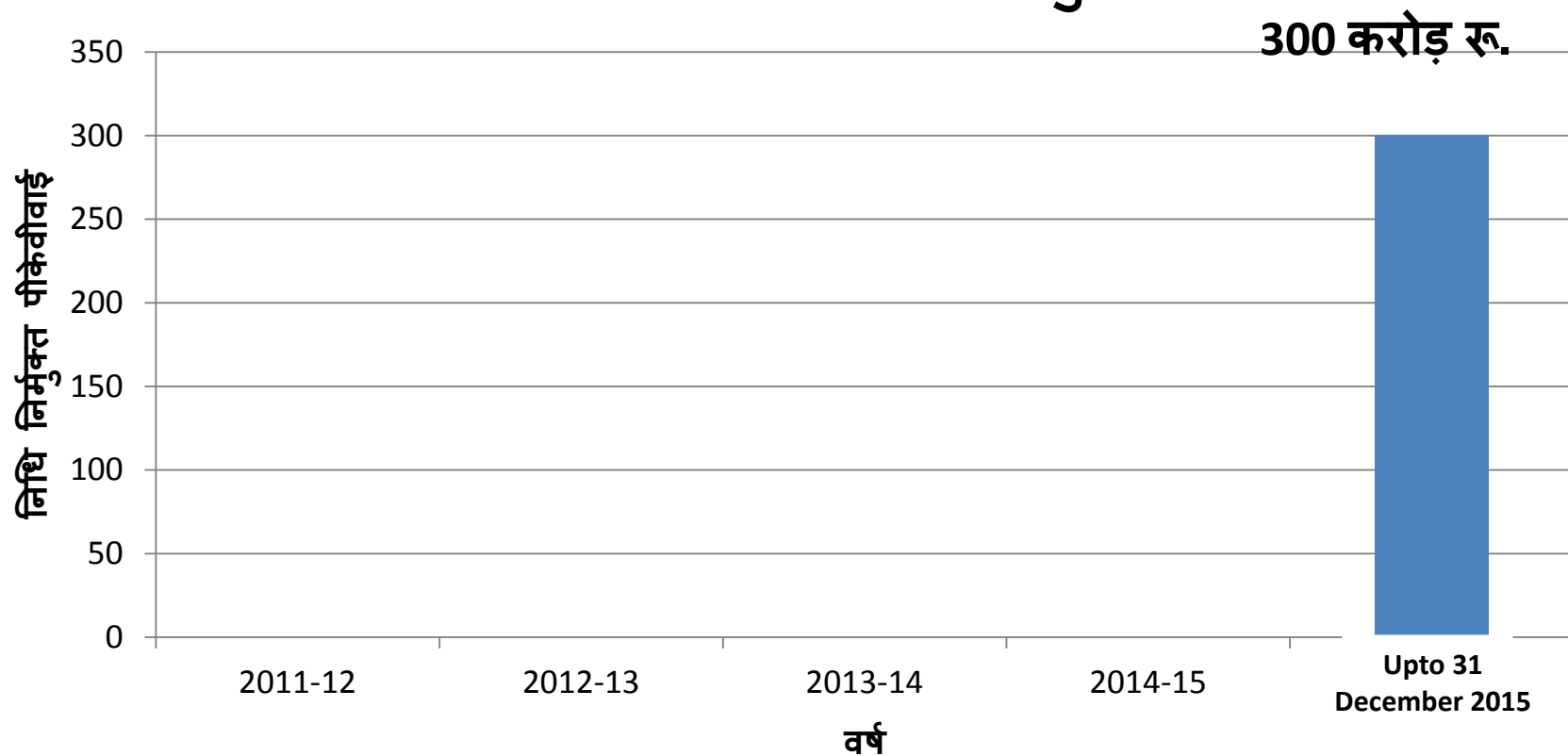
परम्परागत कृषि विकास योजना

जैविक कृषि



जैविक कृषि के लिए कोई स्कीम नहीं थी। केंद्र सरकार की नई स्कीम परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई।

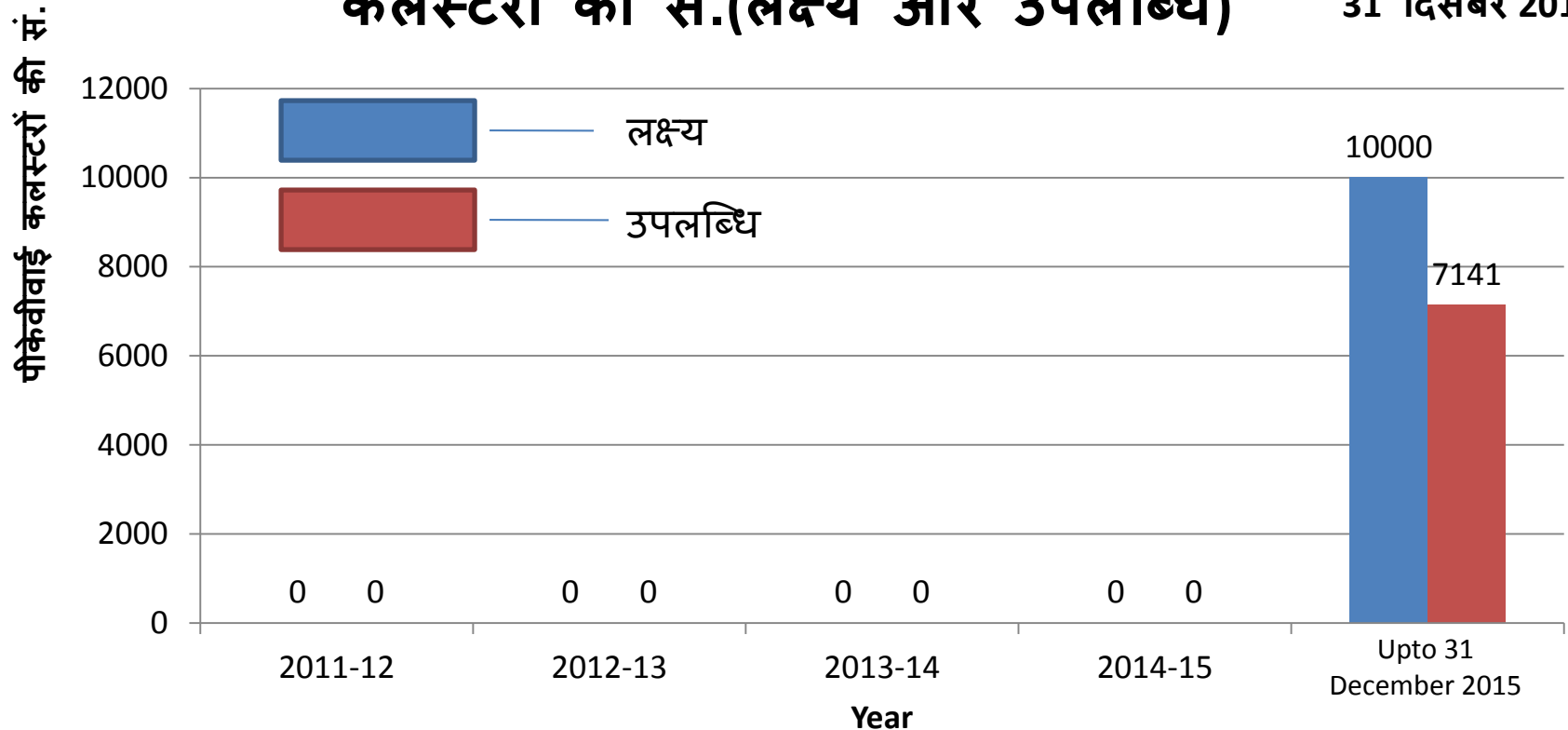
परम्परागत कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के लिए निर्मुक्त निधि



1. सरकार मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. नई योजना परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) वर्ष 2015-16 से जैविक समूहों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए कुल परिव्यय 300 करोड़ रुपये 2015-16 में आवंटित।

पीकेवीवाई के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में कलस्टर्स की सं.(लक्ष्य और उपलब्धि)

31 दिसंबर 2015



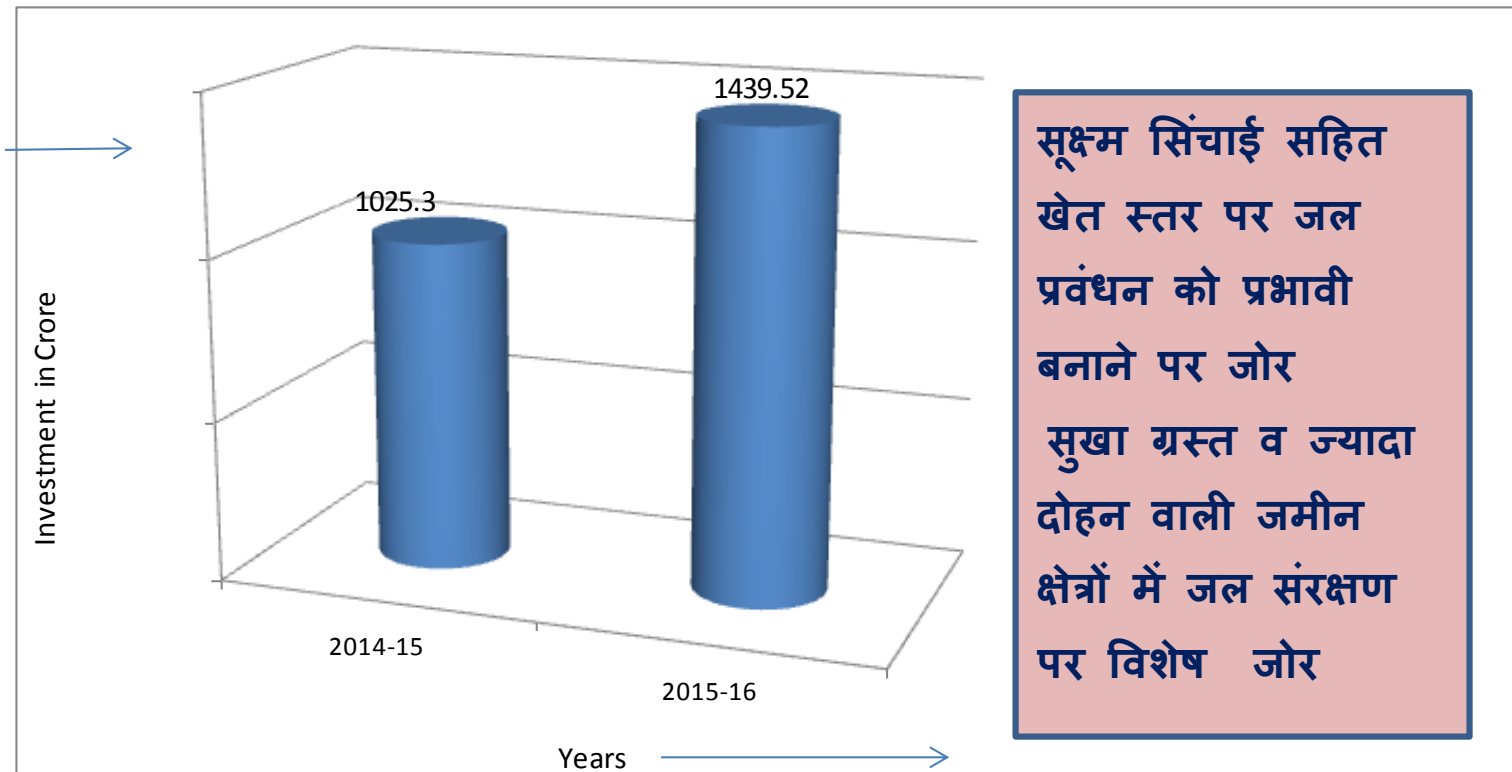
50 एकड़ भूमि होने के 50 से अधिक किसानों के समूह पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10000 समूहों के लक्ष्य की तुलना में 7141 समूहों को 31.12.2015 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

- ₹ 5,300 करोड़ का आवंटन किया!
- इस योजना का लक्ष्य - सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन, वितरण, नेटवर्क एंड फार्म लेवल एप्लीकेशन में अंत से अंत तक समाधान करना है!
- सिंचाई के स्रोतों का निर्माण करना!

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

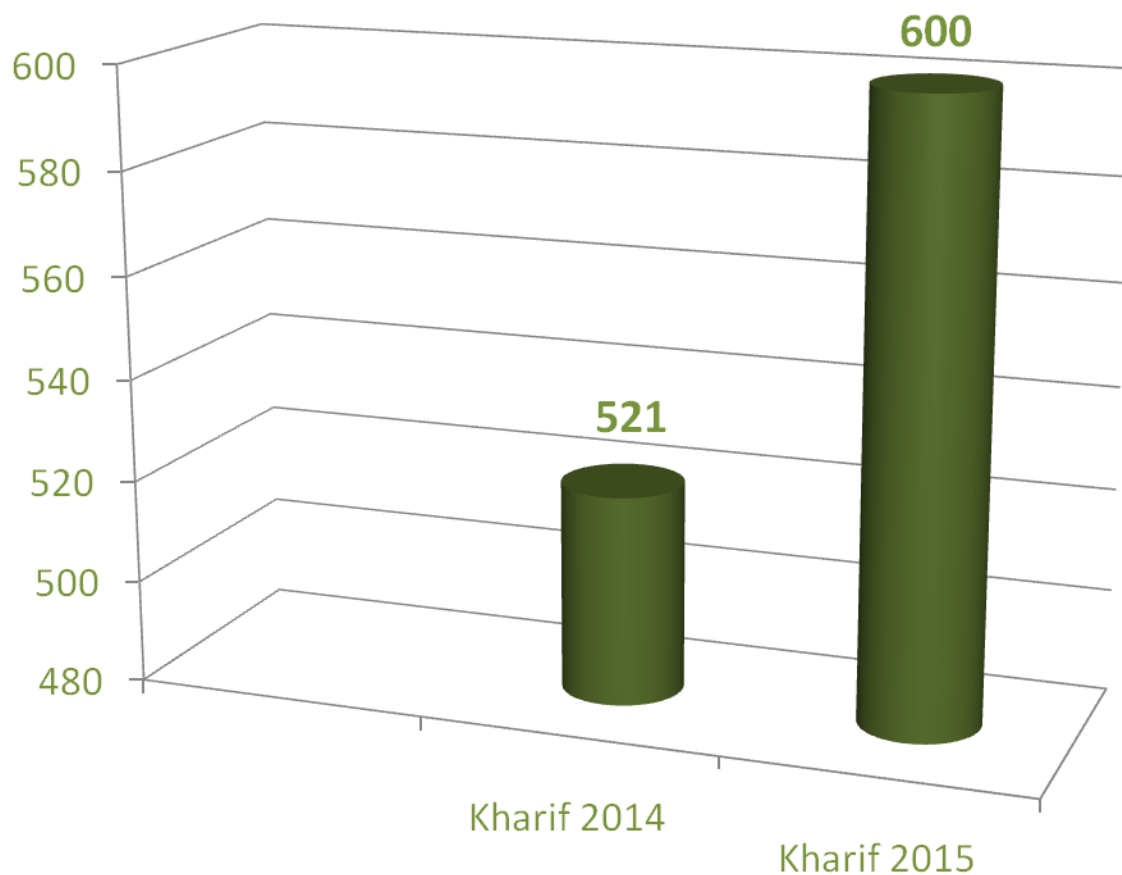
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में जल प्रबंधन हेतु बजट प्रावधान में बढ़ोतरी



एन डी ए सरकार के एक वर्ष में 40 % की बढ़ोतरी

प्राकृतिक आपदाएं

आकस्मिकता योजनाओं के अंतर्गत जिलें

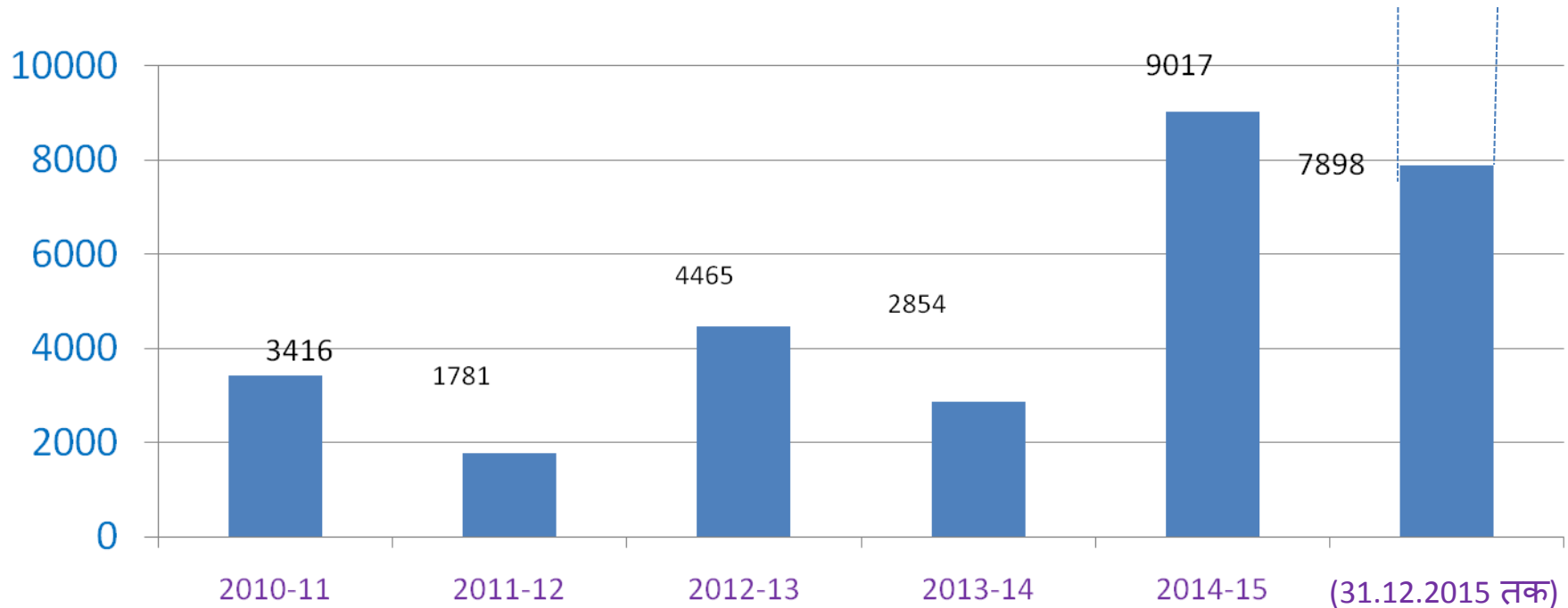


आकस्मिकता
योजना के
अंतर्गत देश में
खरीफ, 2015
के दौरान 20
नए जिलों के
साथ 600
जिलें कवर
किए गए थे।

प्राकृतिक आपदाएं

वर्ष 2010-11 से 2013-14 एवं 2014-15 एवं 2015-16 तक के वर्षों के लिए और सूखे, ओलावृष्टि और कीट आक्रमण की स्थिति में एनडीआरएफ से अनुमोदित राशि

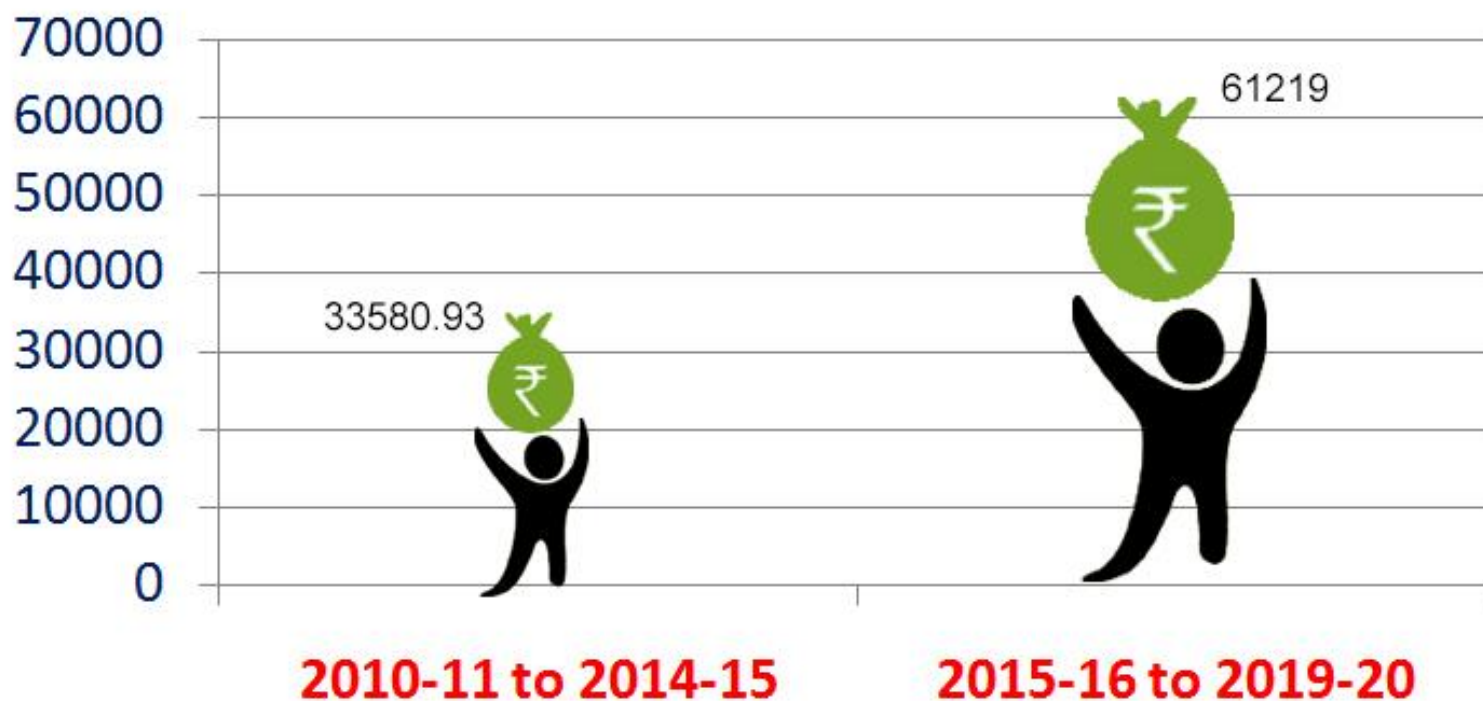
Amount in
Rs.crore



4 साल (2010-11 से 2013-14) के दौरान दी गई सहायता - रुपये 12516 करोड़
राजग सरकार द्वारा 18 महीने (अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015) के दौरान दी गई सहायता =
रु 16,916 करोड़
2015-16 में 6 राज्यों (ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान)
को सहायता प्रदान करने हेतु प्रक्रिया जारी है

प्राकृतिक आपदाएं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष

Rs. Crore



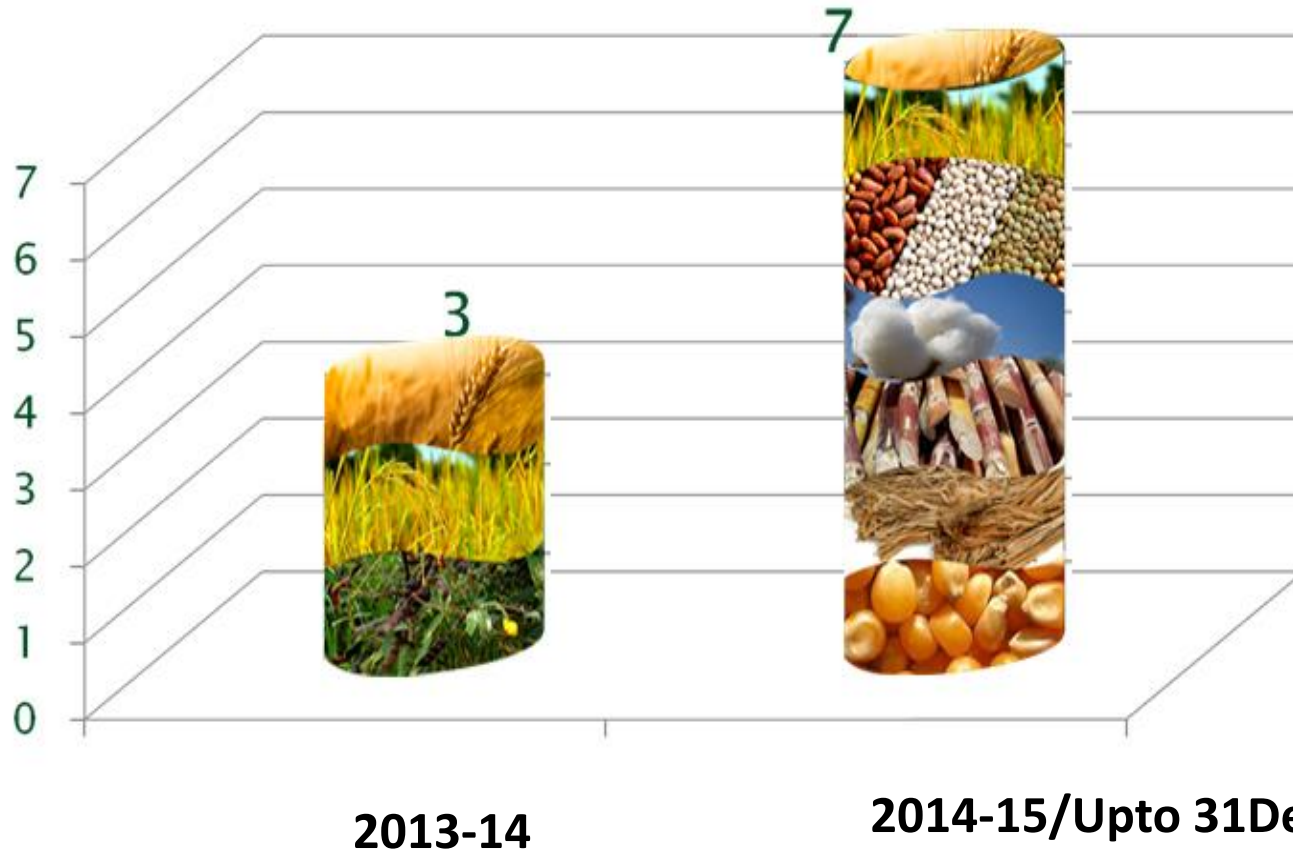
एसडीआरएफ के तहत आवंटन दोगुना कर दिया गया है, यह निधि आपदा से निपटने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को मदद करती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)



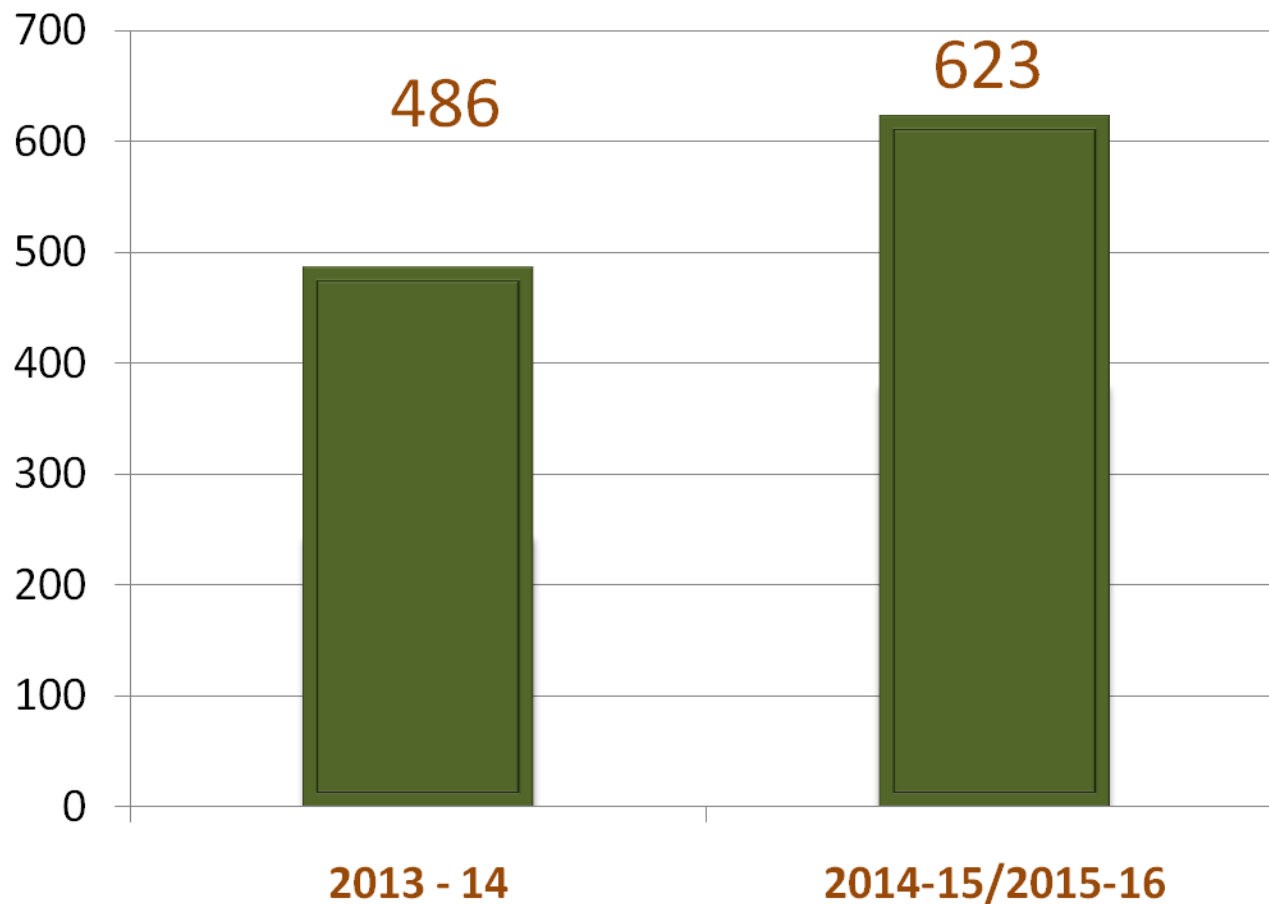
1. सात फसलों - चावल, गेहूं, दलहन, जूट, गन्ना, कपास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कवर मोटे अनाज।
2. दालों के विकास के लिए 50% एनएफएसएम को समर्पित किया गया है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों की खेती जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलों की संख्या



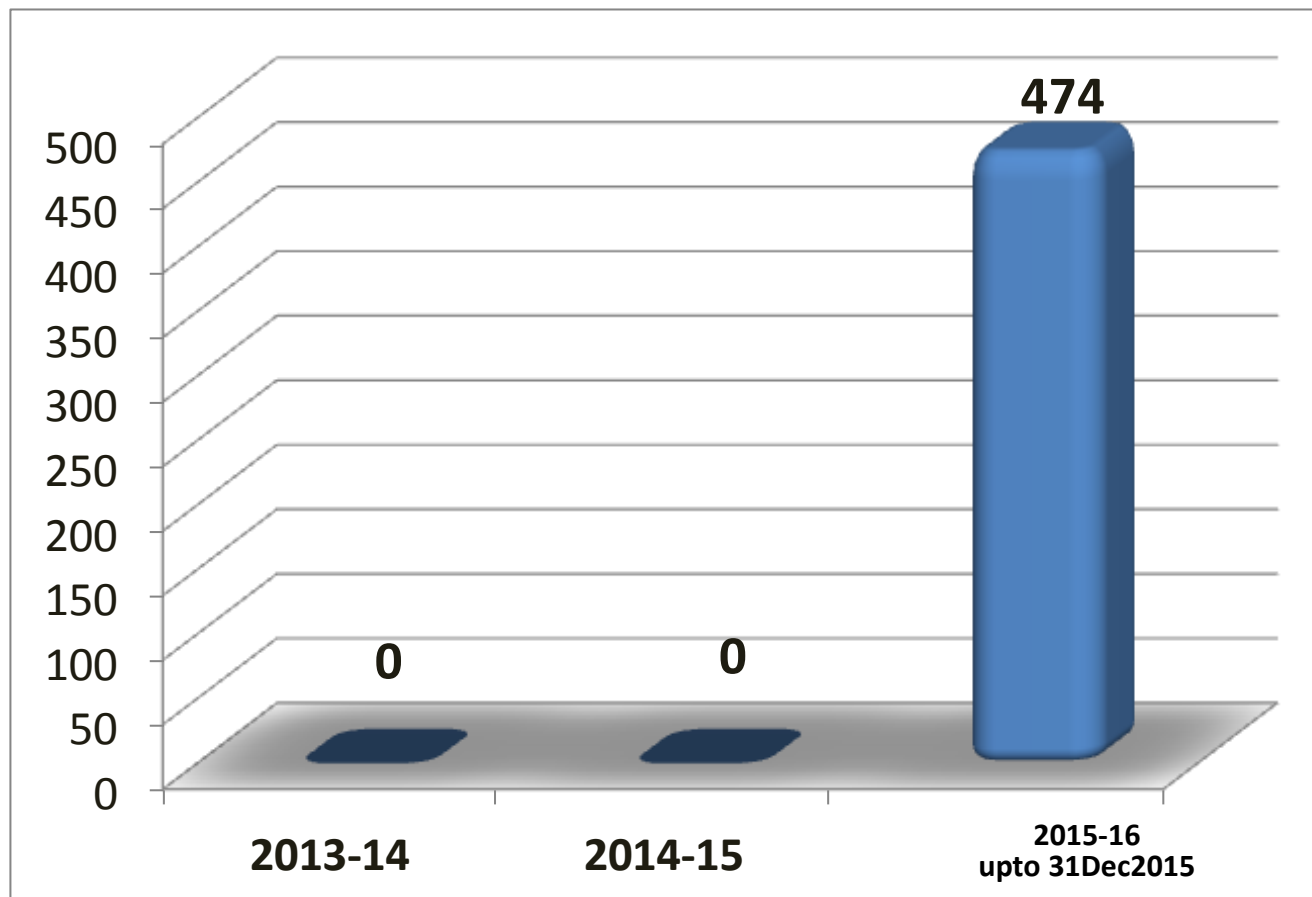
इसके अलावा चावल, गेहूं और दलहन; मूँटे अनाज, गन्ना, जूट और कपास एनएफएसएम के तहत शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या



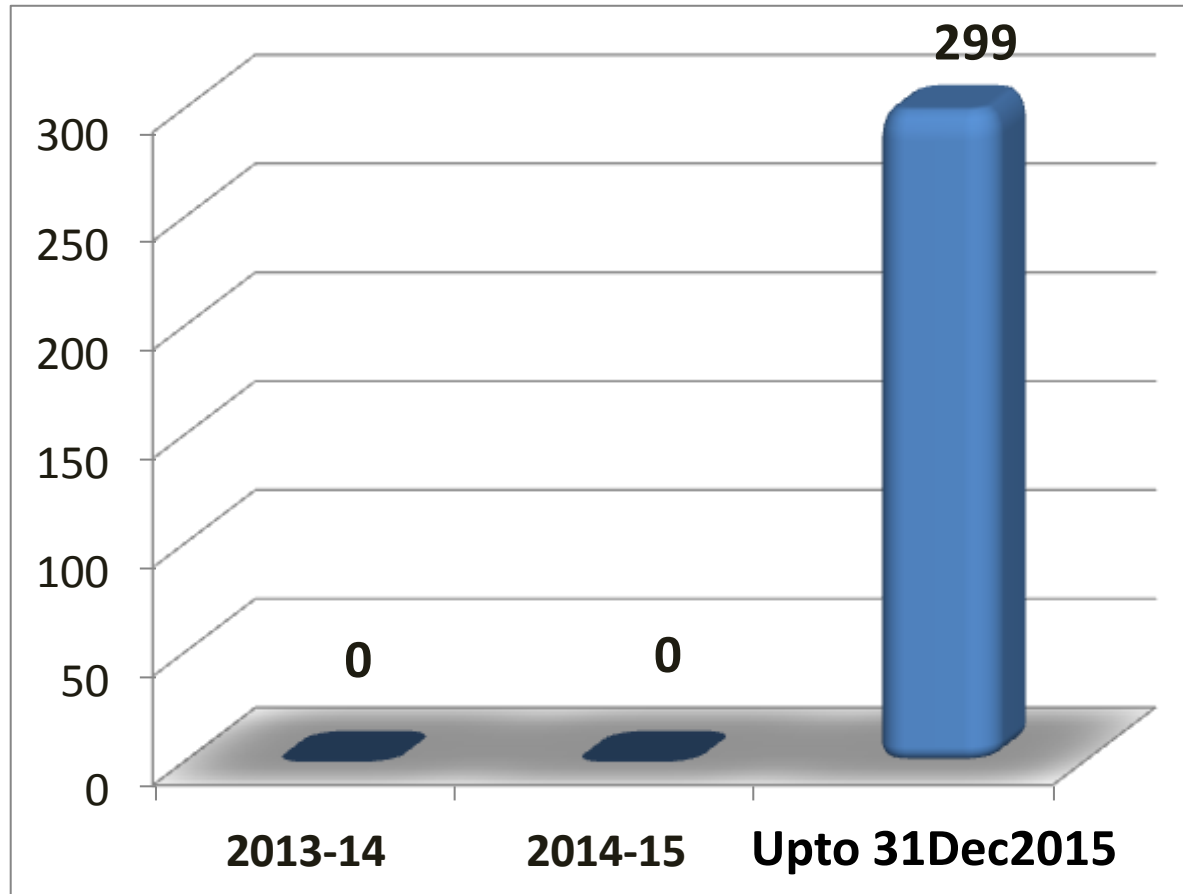
पिछले 2 वर्षों में एनएफएसएम के प्रसार काफी बढ़ गया है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत दलहन प्रदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्रों की भागीदारी



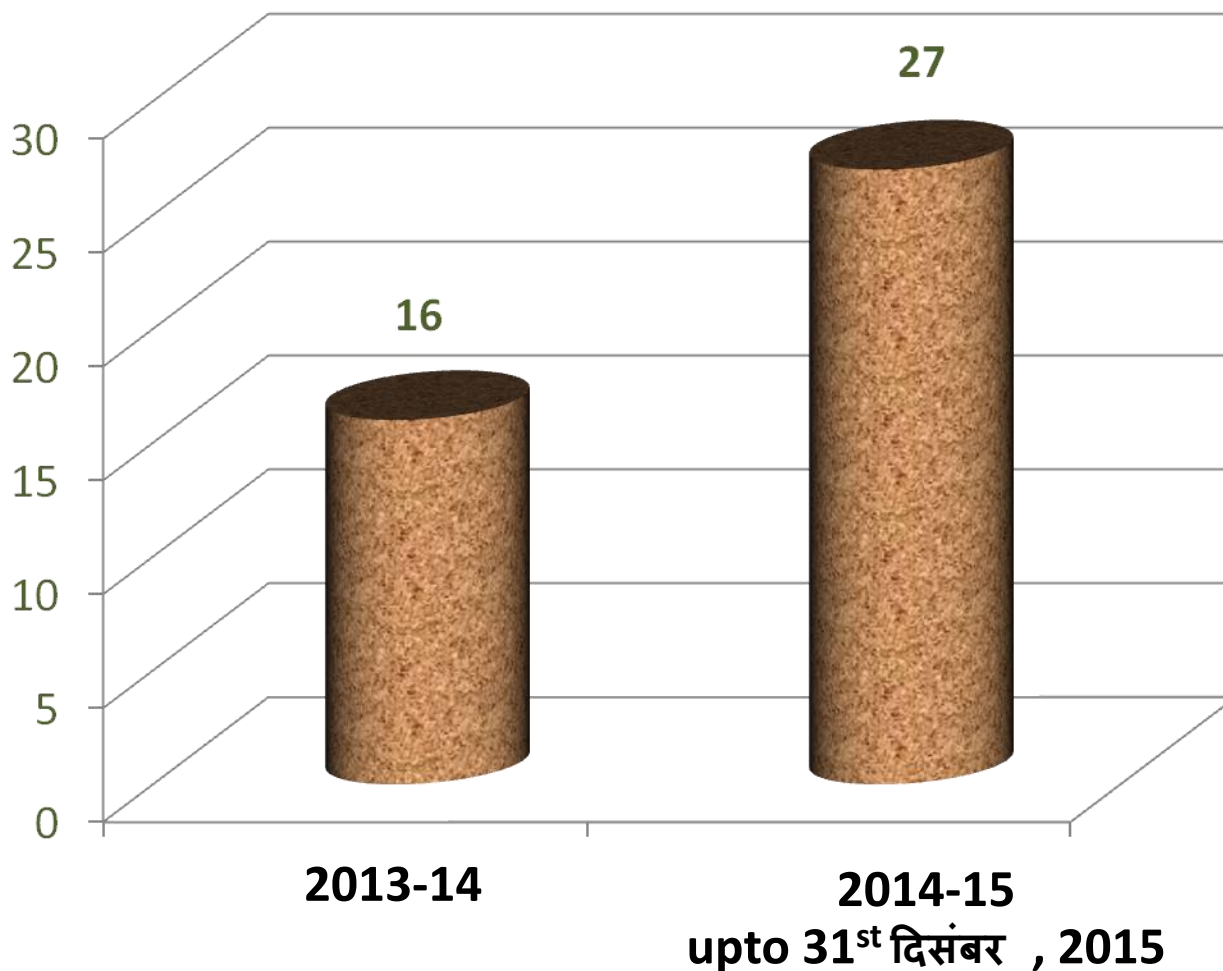
नई तकनीक के शीघ्र व प्रभावी प्रसार के लिए वर्ष 2015 -2016 में पहली बार दलहन प्रदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्रों को शामिल किया गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत तिलहन प्रदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्रों की भागीदारी



नई तकनीकी के शिघ्र व प्रभावी प्रसार के लिए वर्ष 2015 -2016 में पहली बार तिलहन प्रदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्रों को शामिल किया गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन में शामिल राज्य



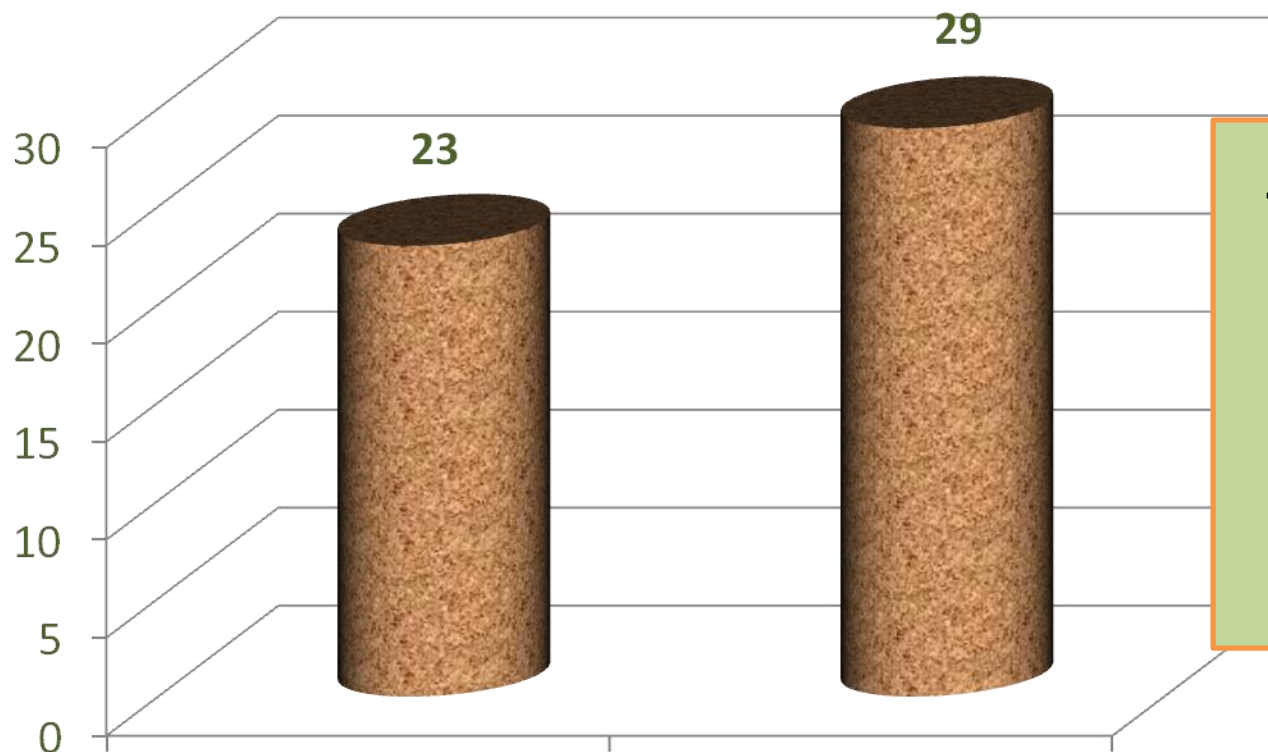
पिछली सरकार की अपेक्षा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक राज्यों को शामिल किया गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन में शामिल जिले



27 राज्यों के सभी जिलों अव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिसन-दलहन में शामिल किये है

आयल सीड एवं आयल पाम विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन

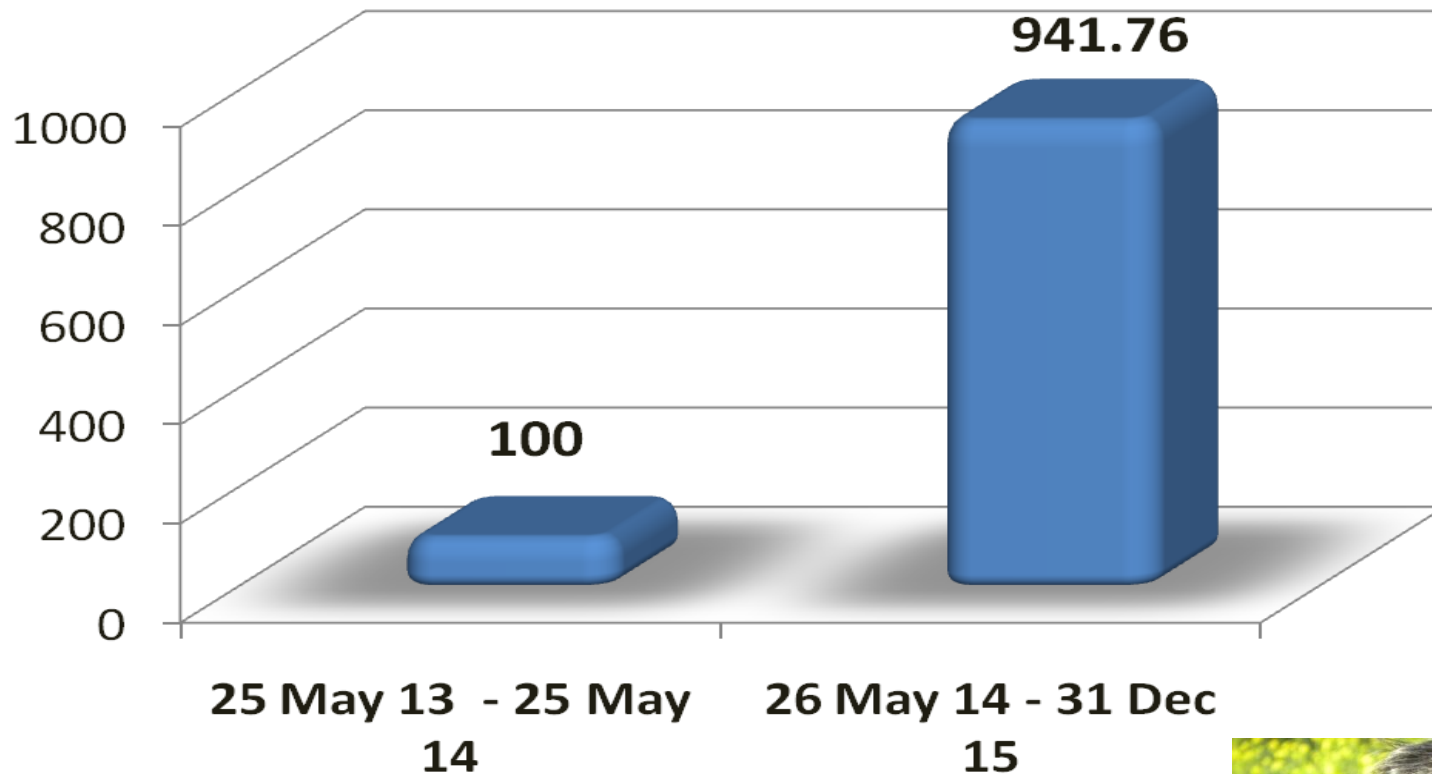


2013-14

2014-15 & 15-16
(31 दिसम्बर 2015 तक)

तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी राज्यों को आयल सीड एवं आयल पाम विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कवर किया गया है।

किसानो को भेजी गयी कृषि सम्बंधित सलाह (एस एम एस की संख्या) नेशनल इ-गवर्नेंस के अंतर्गत



किसानो को भेजी गयी फसल व मौसम संबधी एस
एम एसों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गयी



फसल बीमा एवं कृषि मंडी - मोबाइल एप्लिकेशंस



Crop Insurance

Premium Calculator

Sum Insured Details

Multi language Support

Company Contact Details

Department of Agriculture & Cooperation
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare,
Government of India

Crop Insurance mobile app can be used to calculate the Insurance Premium for notified crops based on area, coverage amount and loan amount in case of loanee farmer. It can also be used to get details of normal sum insured, extended sum insured, premium details and subsidy information of any notified crop in any notified area.



SCAN QR
to get the APP

Available on Google
Play Store

Department of Agriculture & Cooperation and Farmers Welfare,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India



AGRIMARKET

We are getting your location...

Markets Under 35 (Kms.)

- Khoya Market, Kashmiri Gate (6 km)
- Flower Market, Okhla (10 km)
- Shahdara (10 km)
- Flower Market, Fatehpuri (Princ ipal Yard, 12 km)
- Flower Market, Canaught Place (Pr, 12 km)
- Azadpur (12 km)
- Keshopur (16 km)
- Fodder Market, Mangolpuri (15 km)
- Noida (20 km)

Department of Agriculture & Cooperation
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare,
Government of India

- Latest mandi prices (market rates).
- Fetches the market price of commodities from markets within the range of 50 km.
- Price of any market and any commodity can be fetched.

AgriMarket mobile app can be used to get the market price of crops in the markets within 50 km of the device's location. This app automatically captures the location of person using mobile GPS and fetches the market price .

There is another option to get price of any market and any crop in case person does not want to use GPS location.



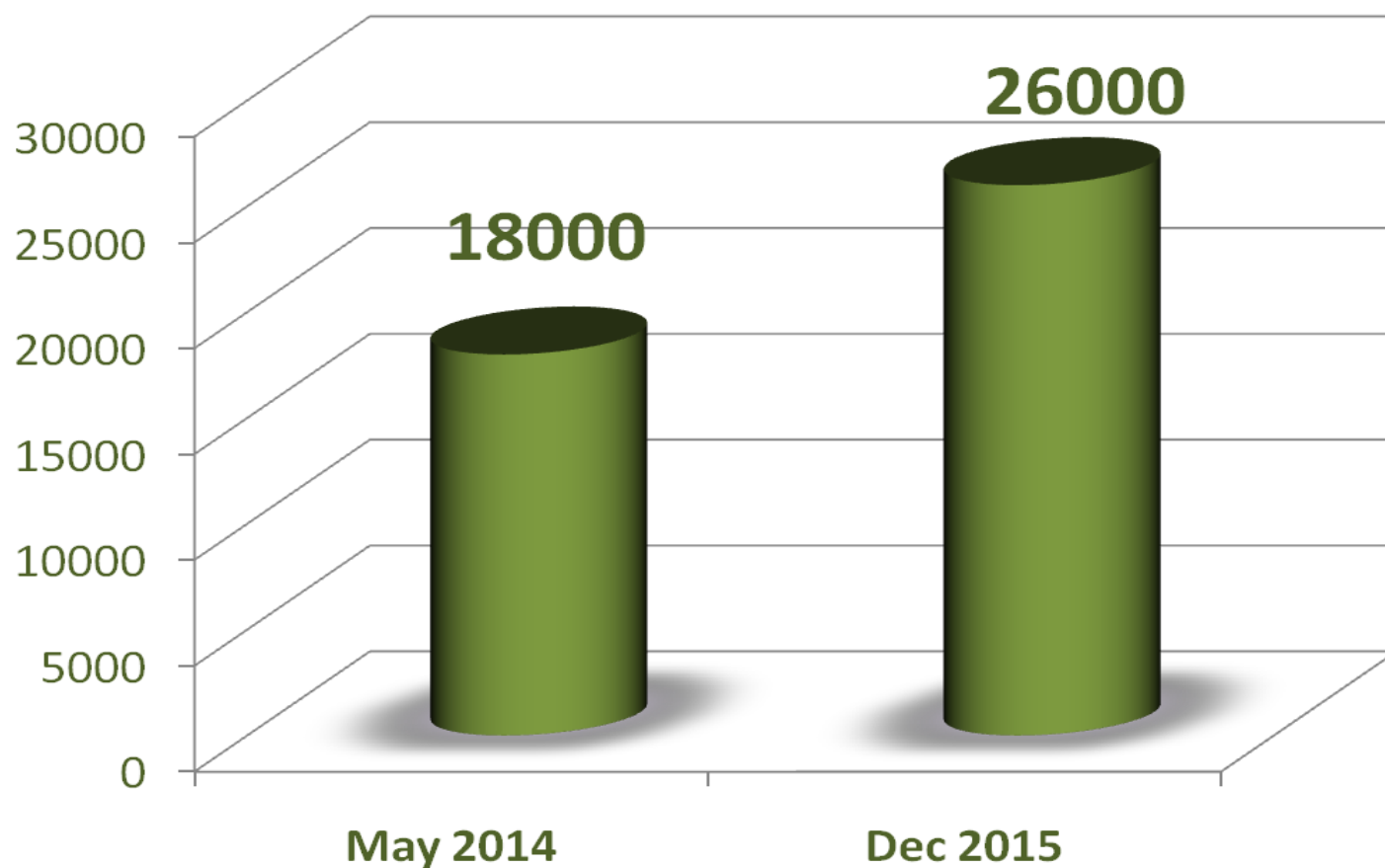
Simply SCAN
to get the APP

Google play

Department of Agriculture & Cooperation and Farmers Welfare,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India

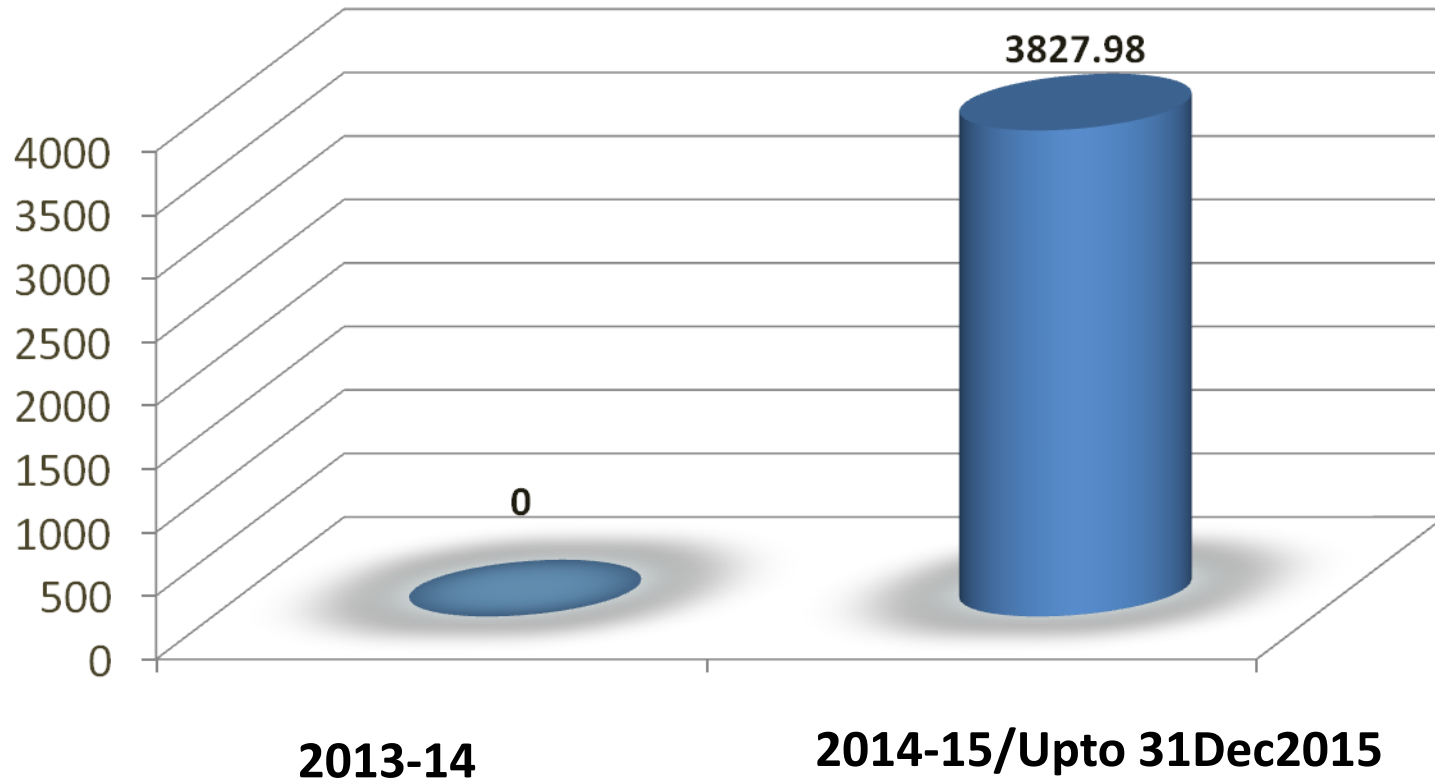
पहली बार वर्तमान सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशंस लांच किये

आत्मा योजना के अंतर्गत विस्तार कर्मिकों की अनुमोदित पद



किसानों को प्रभावी विस्तार सलाह बढ़ाने के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं के पद में 40% की वृद्धि की गयी है

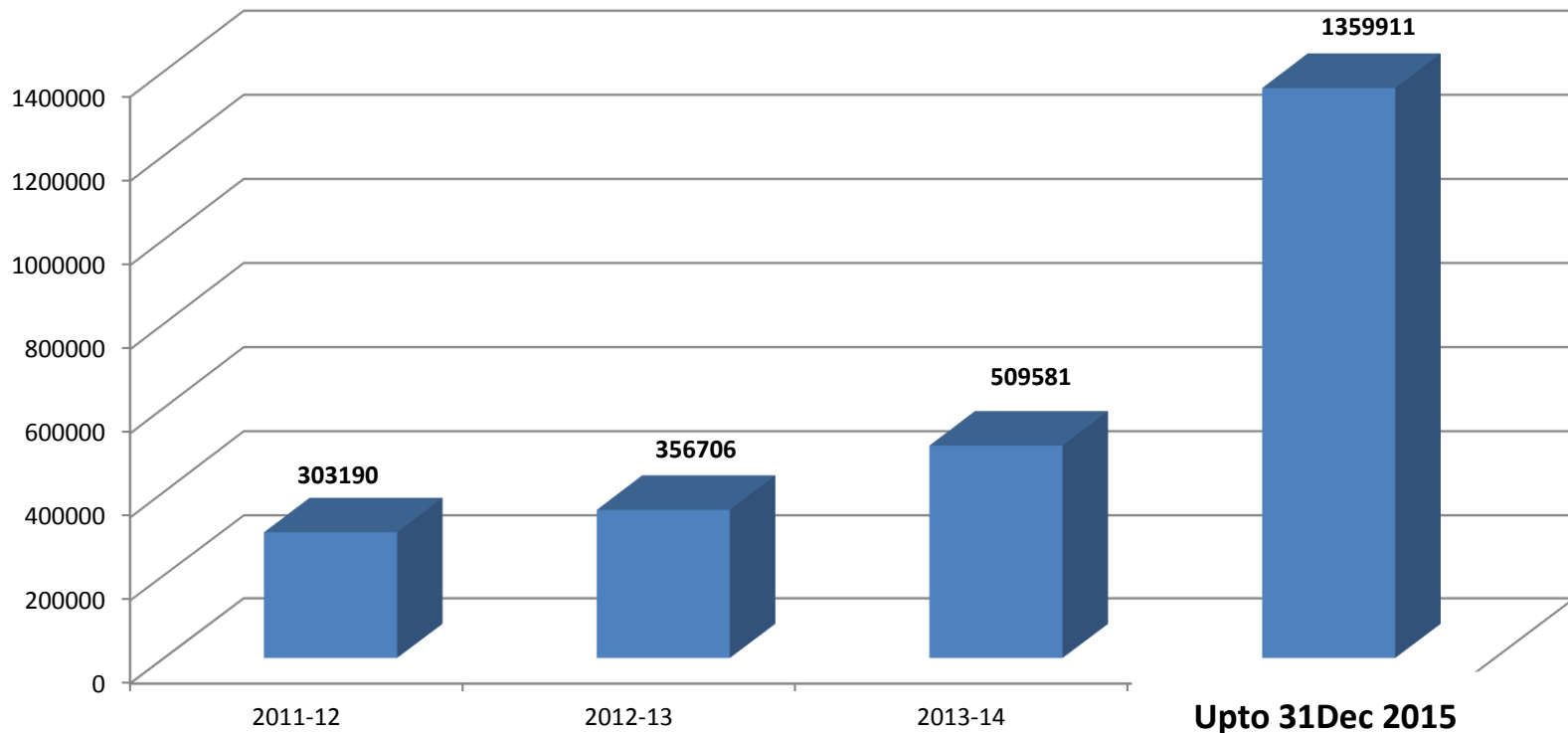
विस्तार सुधारों (आत्मा) में सूचना प्रद्योगिकी का महत्व



- नयी तकनीक के प्रसार के लिए पिको प्रोजेक्टर हस्ताचालित यन्त्र, टेबलेट, इत्यादि के लिए निधि का उपयोग किया गया जबकि पूर्व सरकार के दौरान इसका प्रावधान नहीं था।
- नवंबर 2015 तक 29 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के लिए 3827.98 लाख रु. उपलब्ध करवाये गए।

कृषि में यांत्रिकी करण के लिए उपमिशन किसानों को कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता

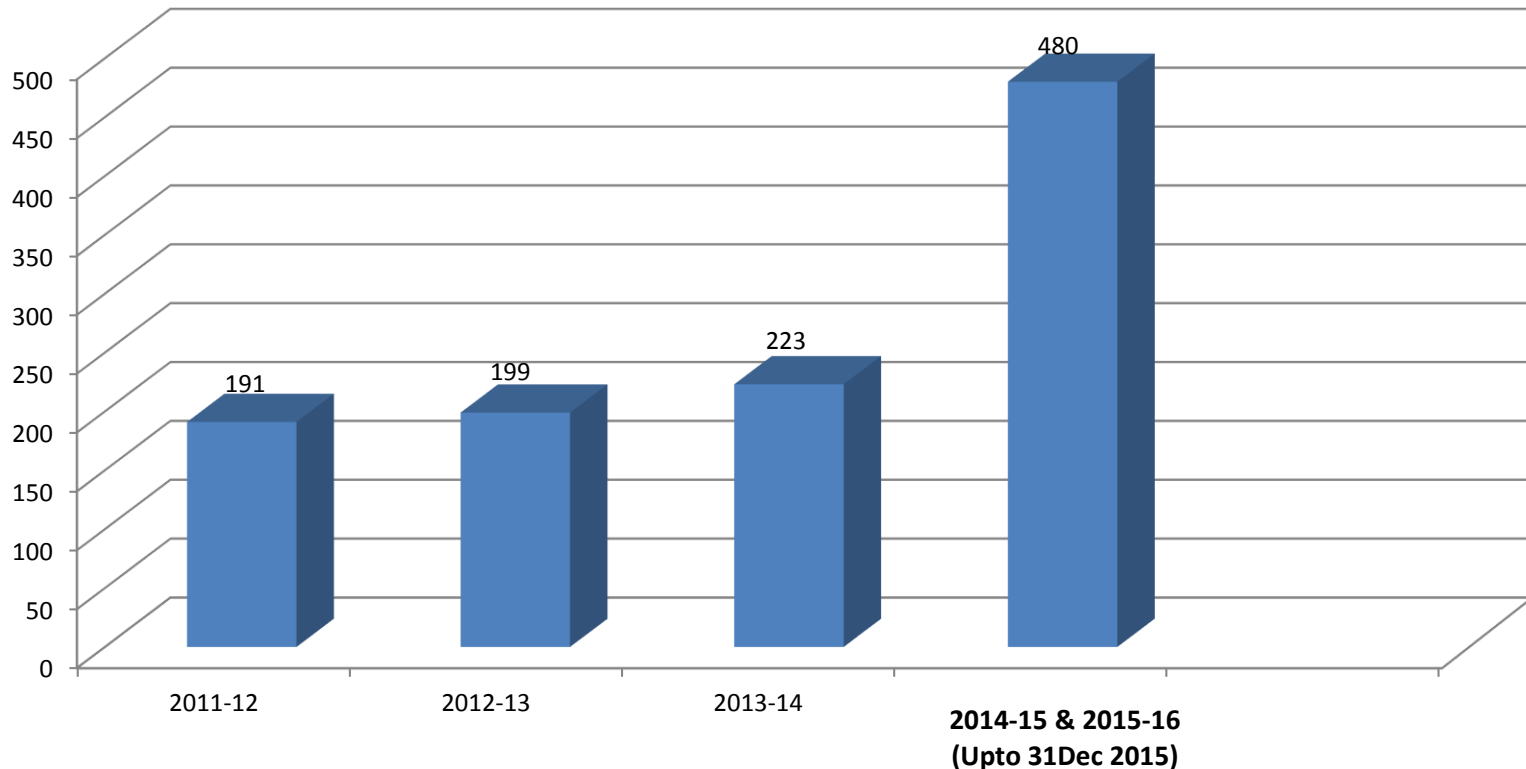
कृषि उपकरण (सं. में)



वर्ष 2013-2014 की तुलना में कृषि मशीनरी और उपकरण, जिसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्वचालित मशीनरी, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण सम्मिलित हैं जिनका कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत किसानों में वितरण किया गया जिसमें अप्रैल 2014 से नवंबर 2015 के दौरान लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

कृषि में यांत्रिकी करण के लिए उपमिशन कृषि मशीनरीयों व्यावसायिक परीक्षणों की संख्या

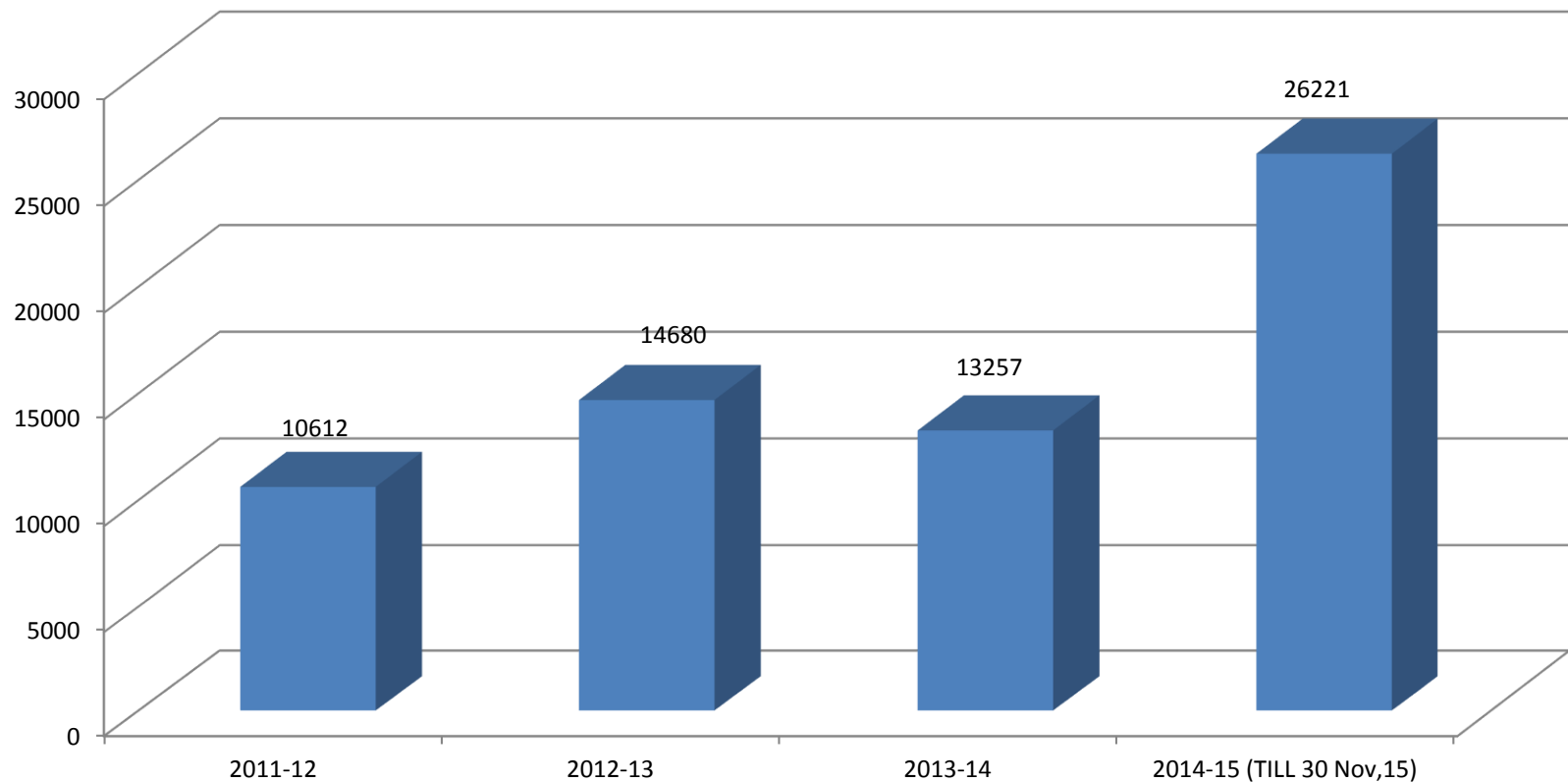
मशीनें एफएमटीटीआईएस पर परीक्षित (संख्या में)



वर्ष 2013-2014 की तुलना में कृषि मशीनरी और उपकरण, जिसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्वचालित मशीनरी, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण सम्मिलित हैं जिनके परीक्षण में अप्रैल 2014 से नवंबर 2015 के दौरान लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है।

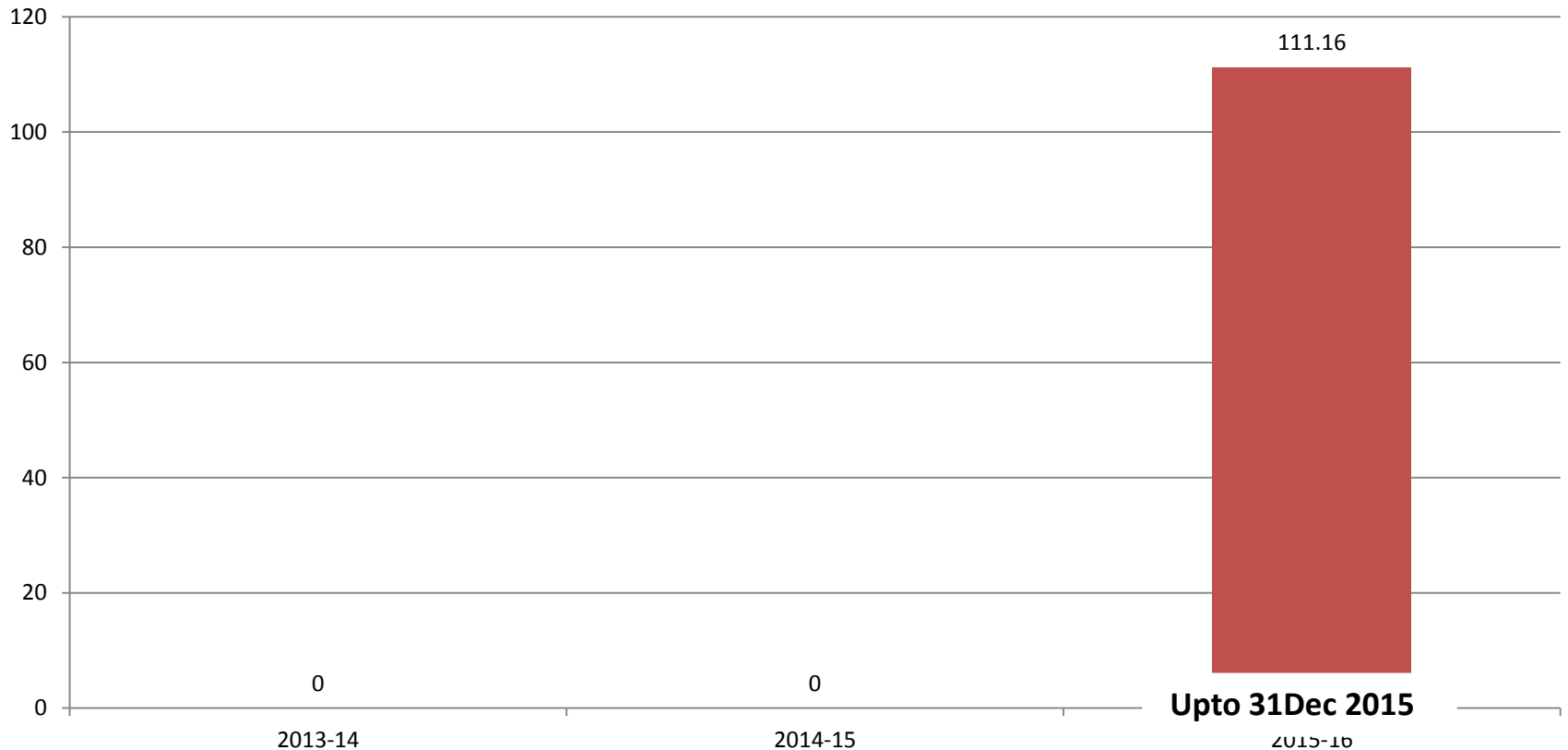
कृषि में यांत्रिकी करण के लिए उपमिशन किसानों को प्रशिक्षण

प्रशिक्षित किसान (संख्या में)



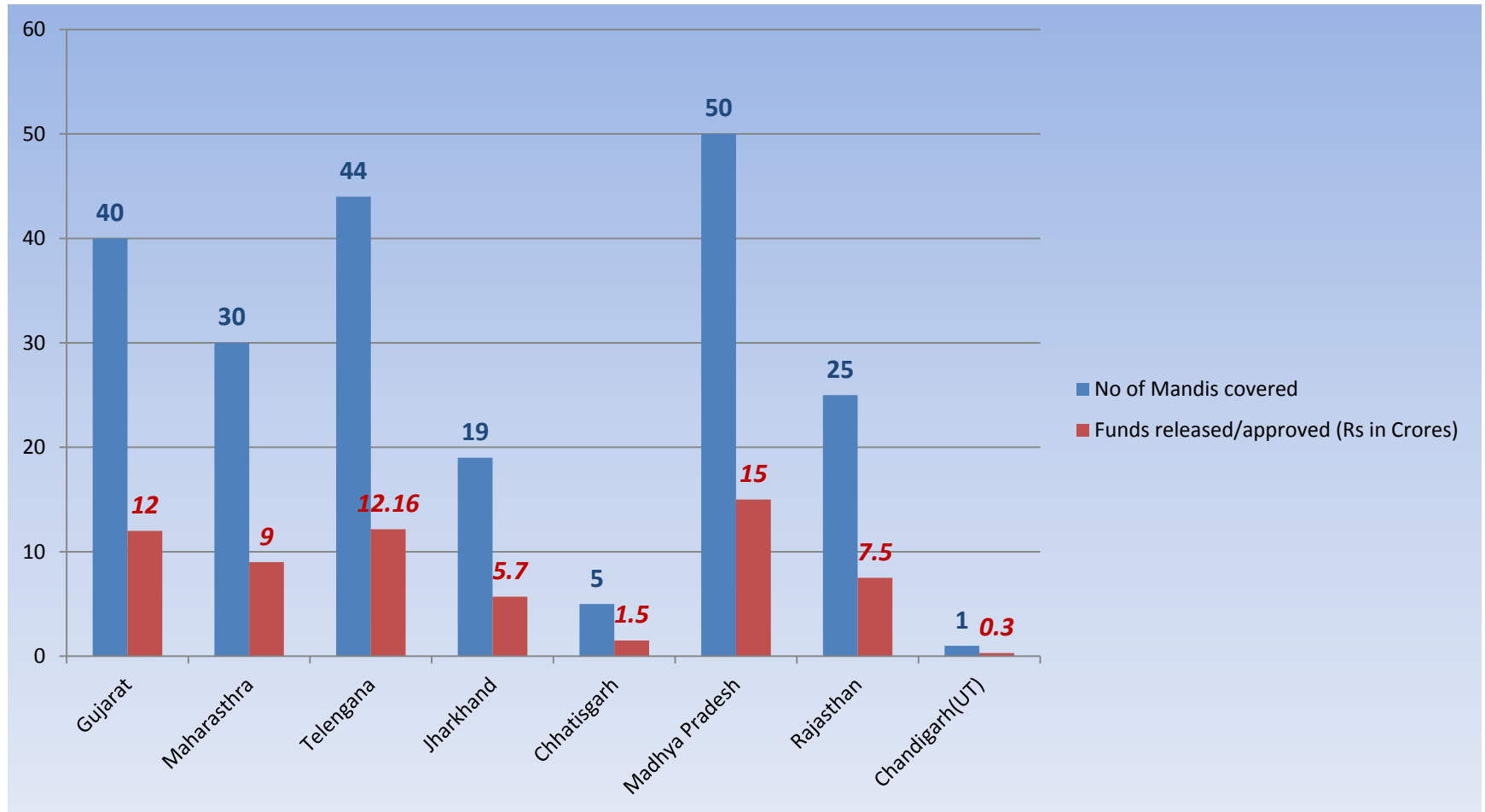
किसानों को विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण की संख्या अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2015 के दौरान लगभग दुगनी हो गयी है

राष्ट्रीय कृषि बाजार : निधि संस्वीकृत(रू. करोड़ में)



- राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (एनएएम); 585 विनियमित थोक बाजार में एक सामान्य ई-बाजार मंच तैयार करने के लिए रू० 200.00 करोड़ की लागत से तीन साल की अवधि के लिए 1 जुलाई 2015 से शुरुआत की गई।
- रणनीतिक साझेदार हेतु 31.12..2015 को रू० 111.16 करोड़ की लागत से 8 राज्यों में 214 मंडियों की स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत राज्यों को आवंटित निधि



अधिक से अधिक राज्य अब राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल होने के लिए उत्सुक

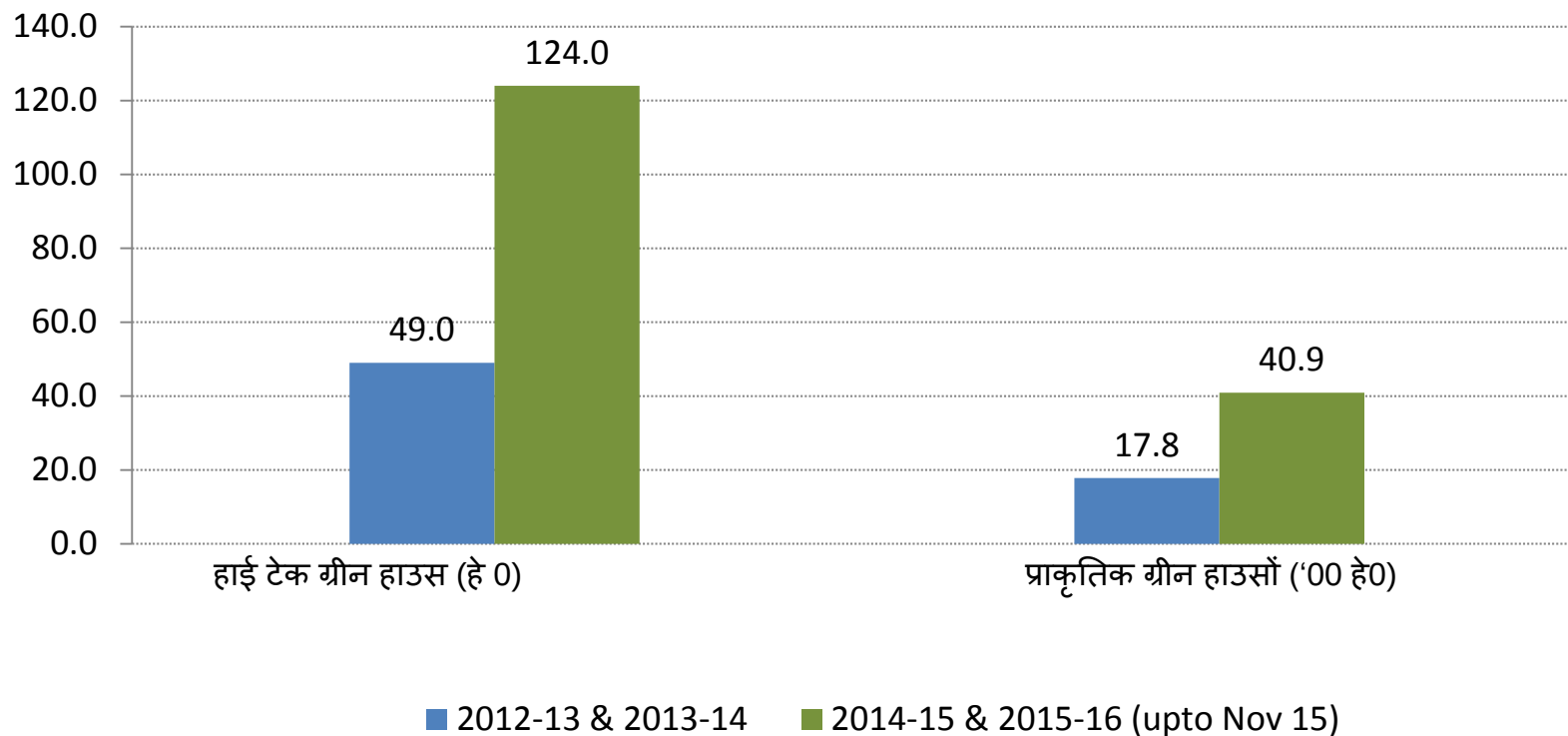
राष्ट्रीय कृषि बाजार : लगभग 20 राज्यों/ संघ शासित राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	मंडियों की संख्या	अनुमोदित / निर्मुक्त सहायता (रु. करोड़ में)
1. गुजरात	40	12 करोड़ रु. निर्मुक्त
2. महाराष्ट्र	30	9 करोड़ रु. अनुमोदित
3. तेलंगाना	44	12.165 करोड़ रु. अनुमोदित
4. झारखंड	19	5.7 करोड़ रु. अनुमोदित
5. छत्तीसगढ़	05	1.50 करोड़ रु. अनुमोदित
6. मध्य प्रदेश	50	15 करोड़ रु. अनुमोदित
7. राजस्थान	25	7.50 करोड़ रु. अनुमोदित
8. चंडीगढ़ (सं.शा.)	01	0.30 करोड़ रु. अनुमोदित

राष्ट्रीय कृषि बाजार का समयबद्ध संचालन

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा :	समय सीमा		
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का निर्माण / होस्टिंग एवं पायलट मंडियों में लॉन्च	1/4/2016		
200 मंडियों में सॉफ्टवेयर का उपयोग	1/4/2016 - 30 /9/2016		
अतिरिक्त 200 मंडियों में सॉफ्टवेयर का उपयोग		1/10/2016 – 31/3/2017	
शेष 185 मंडियों में सॉफ्टवेयर का उपयोग			1/4/2016 - 31/3/2018

समेकित बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच)
वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच हाई-टेक ग्रीन हाउस एवं प्राकृतिक ग्रीन हाउस में दर्ज प्रगति (हेक्टेयर में)

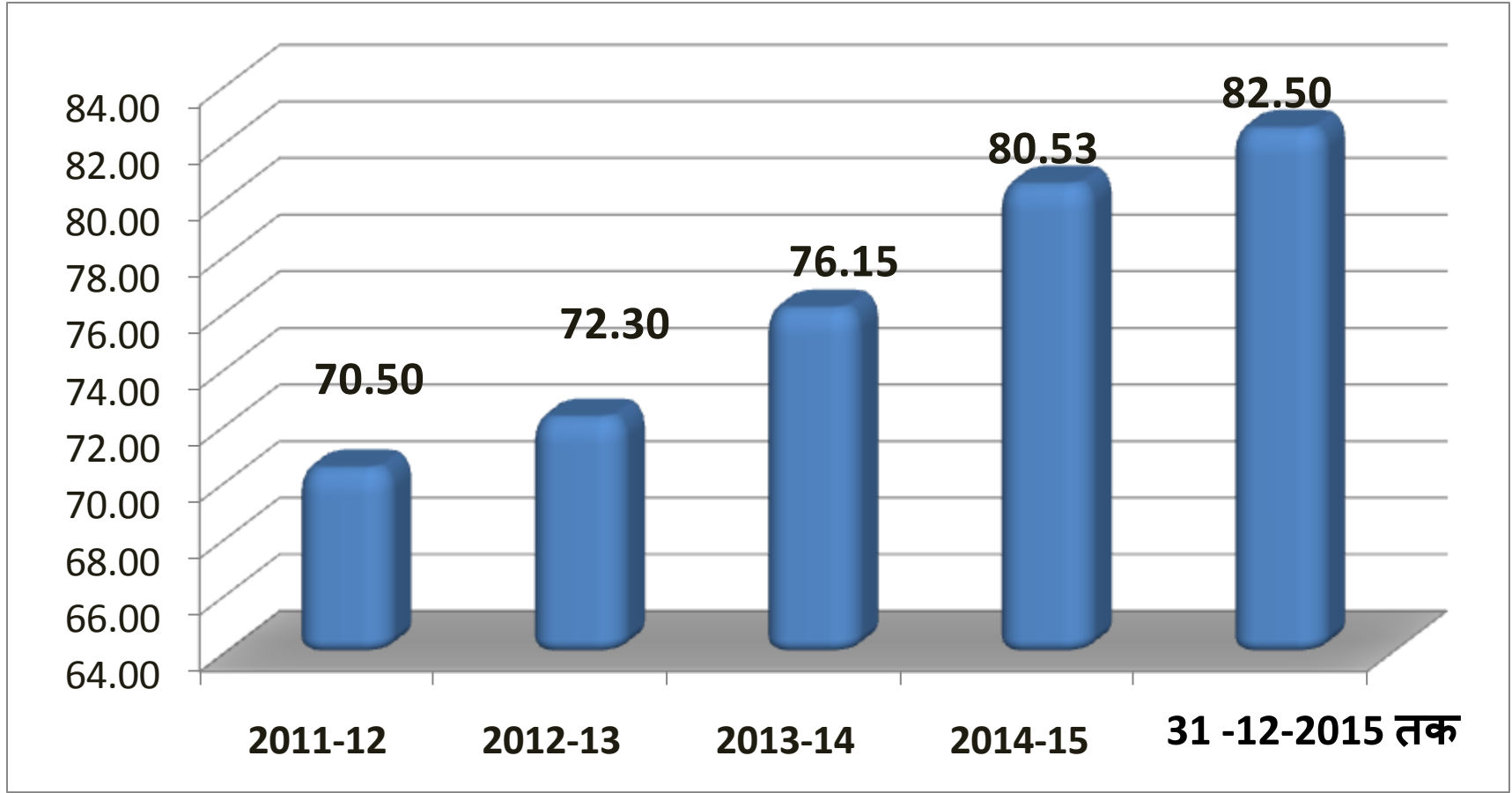


2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 49 हे० पर हाई-टेक ग्रीन हाउस थे जो 2014-15 एवं 2015-16 (नवंबर 2015 तक) बढ़कर 124 हे० हो गयी ।

2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 1780 हे० पर प्राकृतिक ग्रीन हाउस थे जो 2014-15 एवं 2015-16 (नवंबर 2015 तक) बढ़कर 4090 हे० हो गयी ।

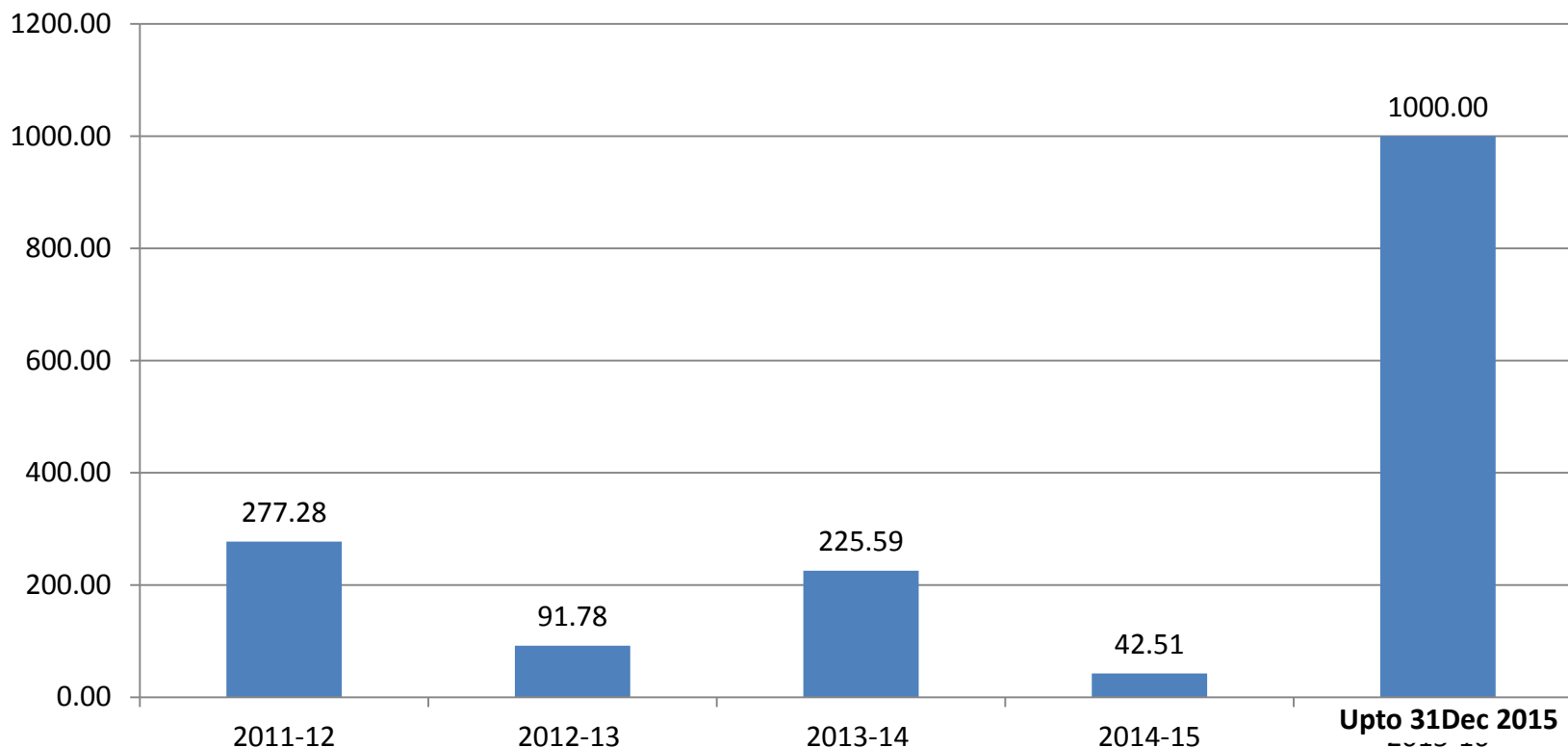
समेकित बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच) : राष्ट्रीय मधु मक्खी बोर्ड (एन बी बी)

विगत 10 वर्षों के शहद उत्पादन के वर्षवार विवरण (एनबीबी की
शुरुआत से)



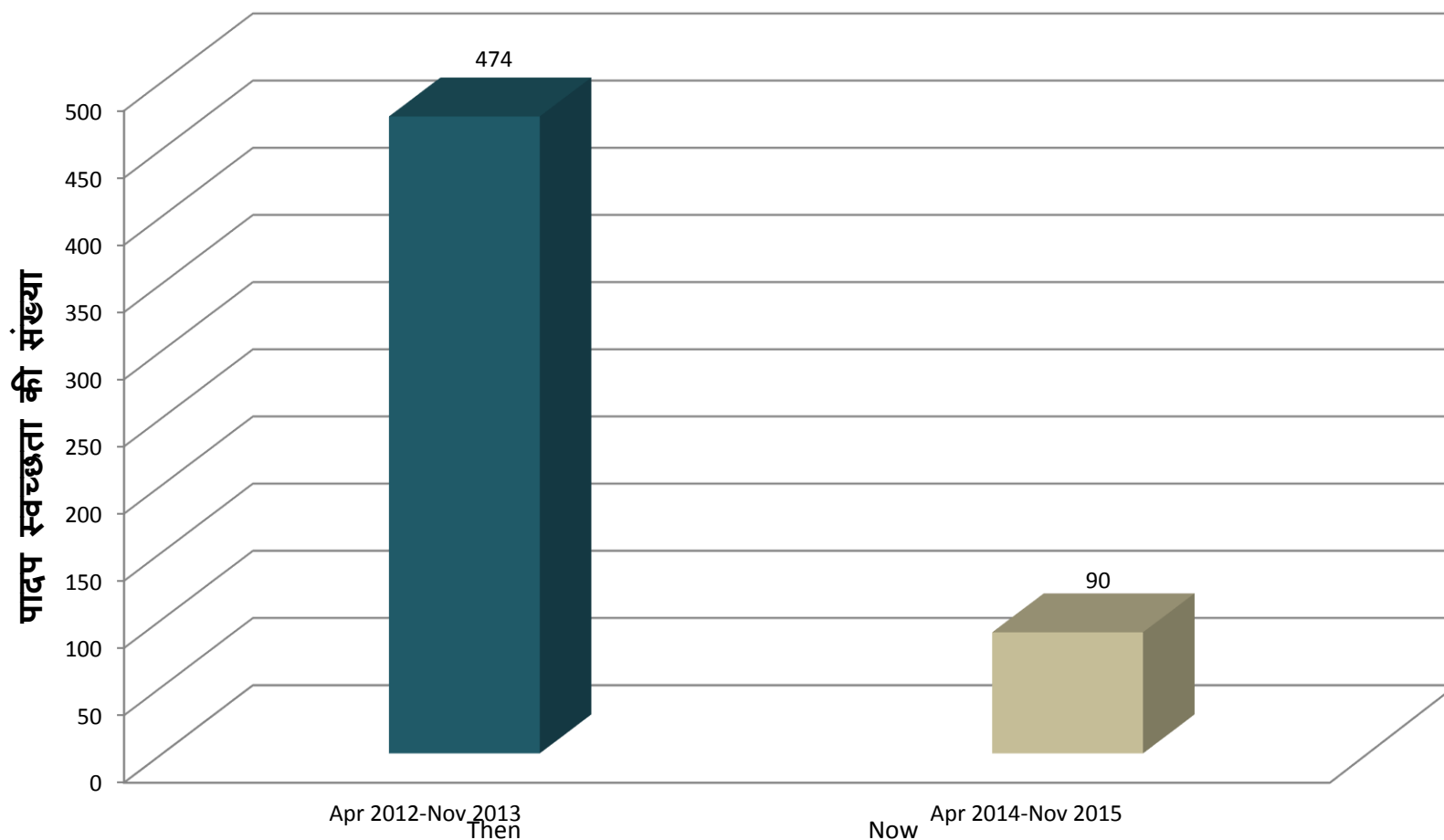
राजग सरकार के पिछले दो वर्षों के दौरान शहद उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई

**समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
एनएचएम/एचएमएनईएच/एमआईडीएच के अंतर्गत अनुमोदित निधियों का वर्षवार ब्यौरा
(31-12-2015 तक)**



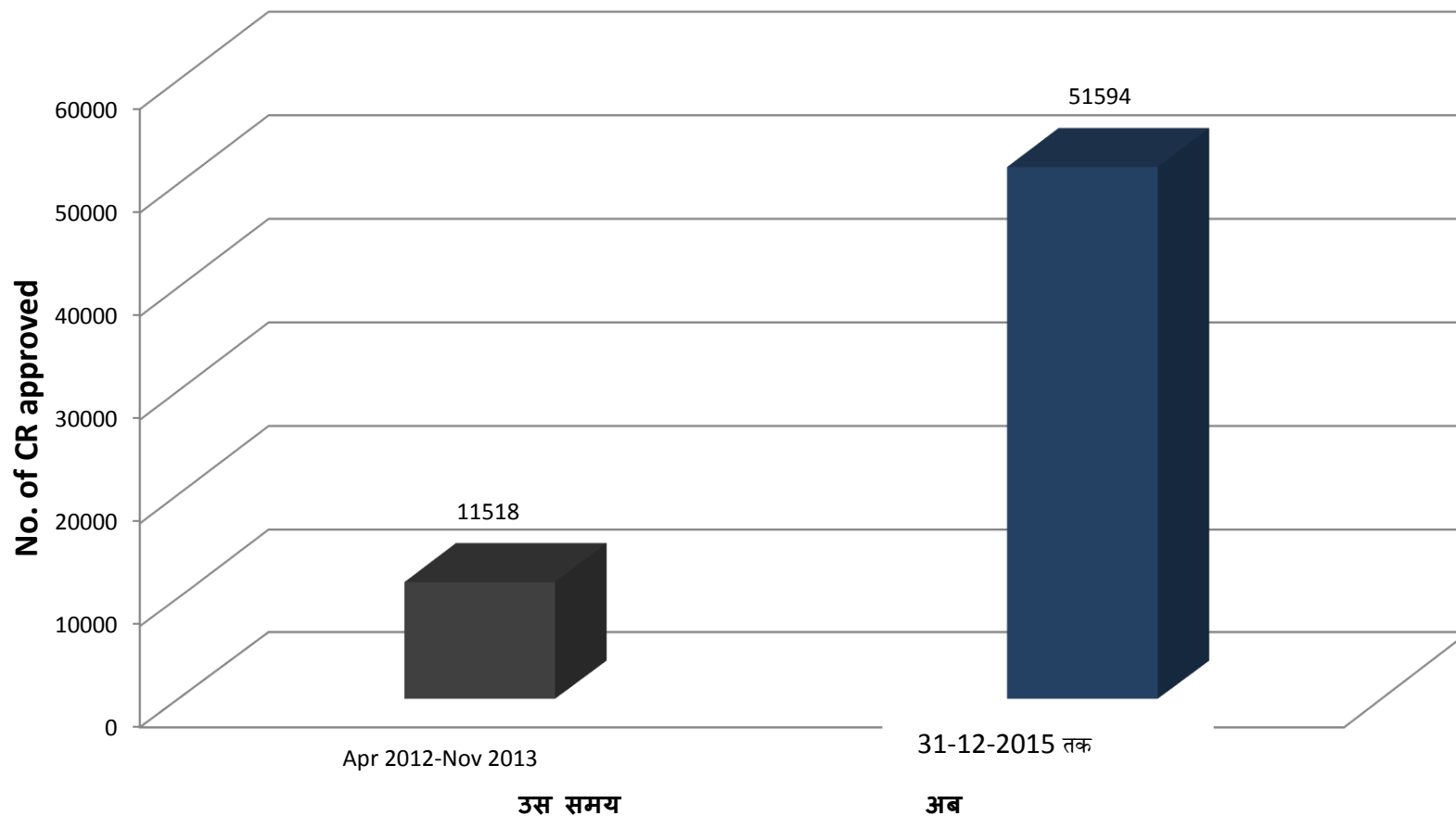
मधुमक्खी पालन के लिए बजट में पिछले दो वर्षों के दौरान 2.25 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गयी ।

पौध संरक्षण : निर्यात प्रमाणीकरण में प्रमुख सुधार



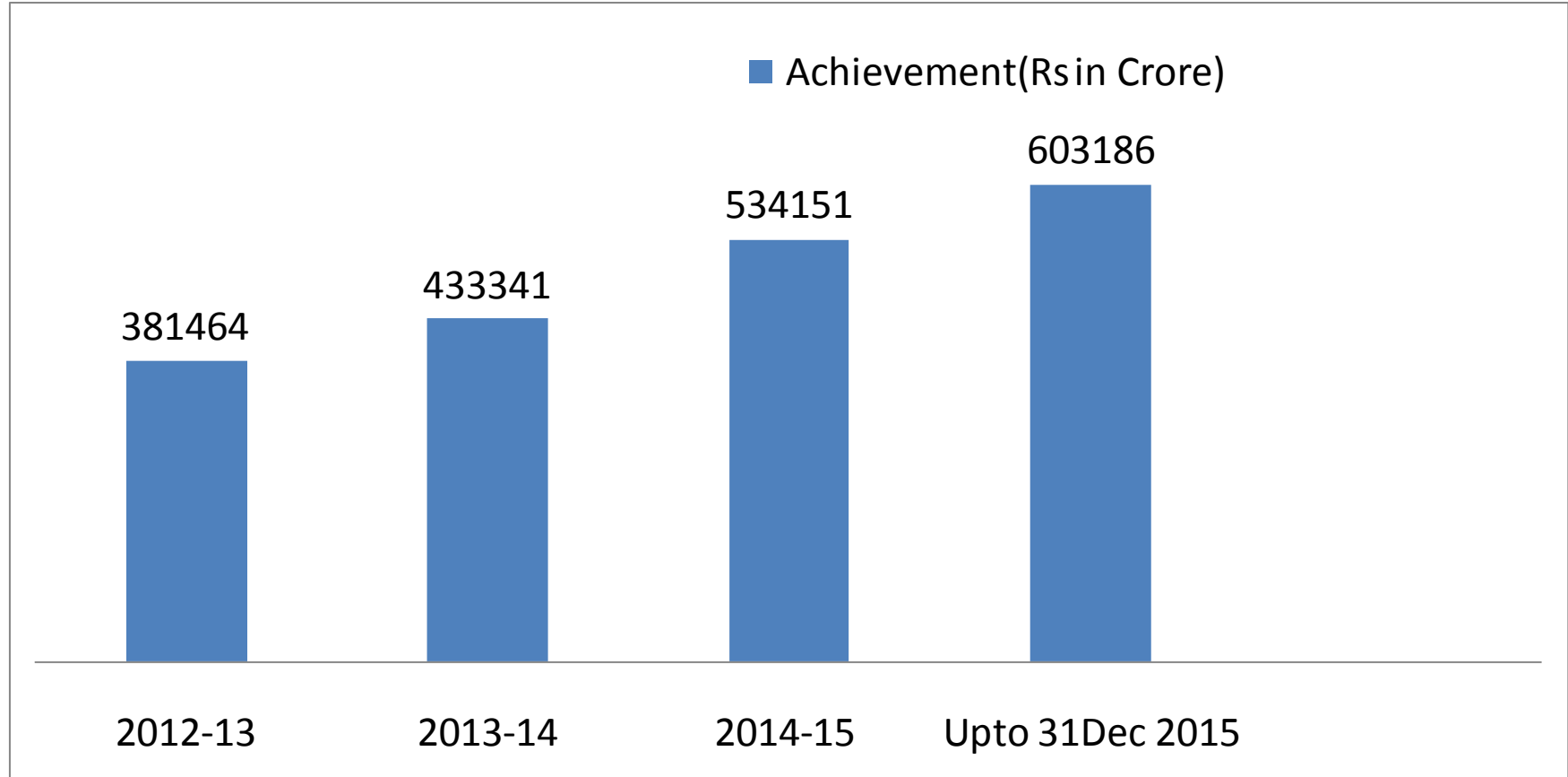
कीटों के कारण यूरोप के लिए भारत से कृषि निर्यात खेप की इंटरसेप्शन की संख्या को पांच गुना कम किया गया है ।

पौध संरक्षण: कीटनाशक पंजीकरण की संख्या



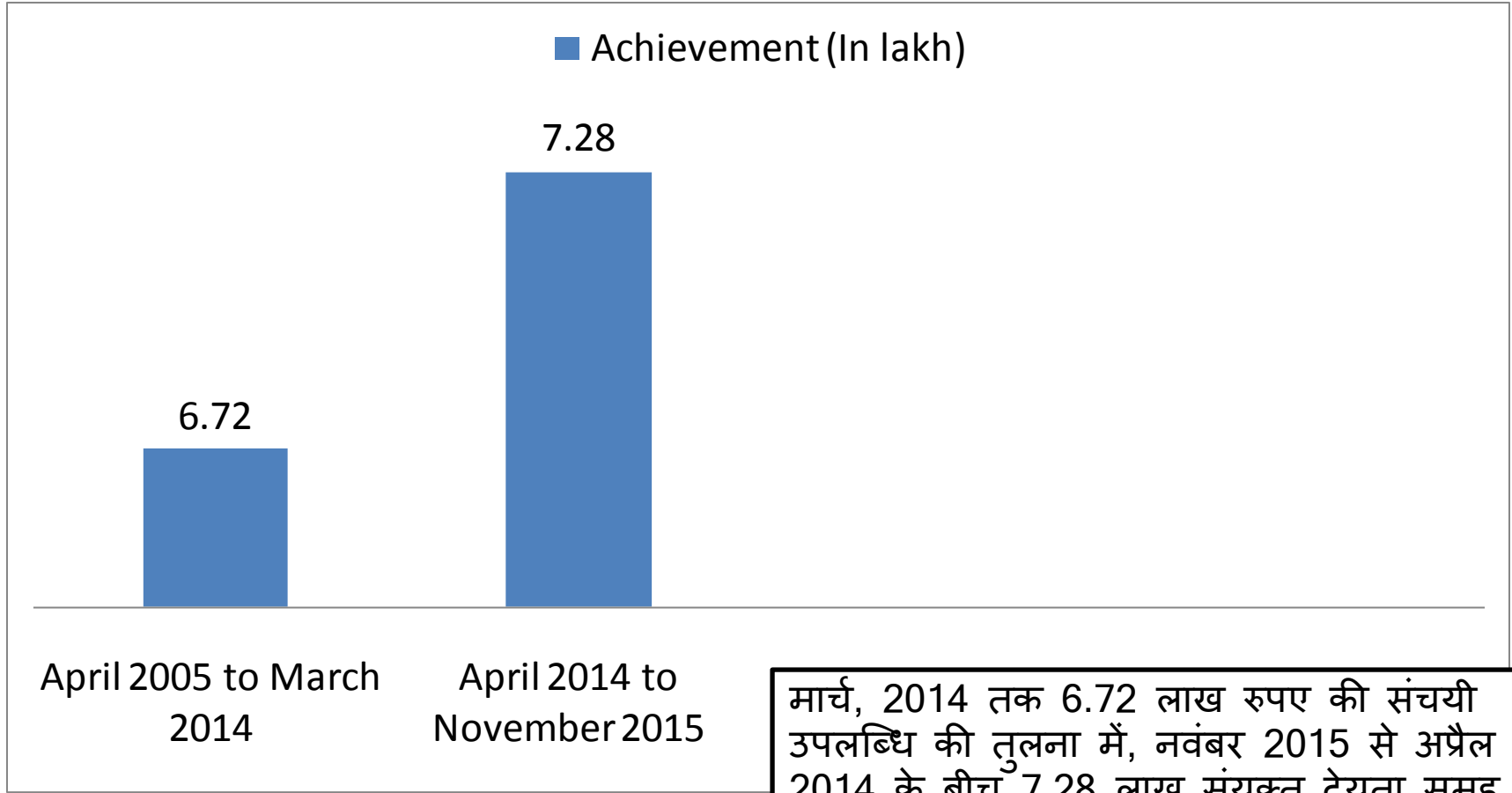
कीटनाशकों के पंजीकरण में 4 गुना अधिक सुधार

किसानों को अग्रिम कृषि ऋण



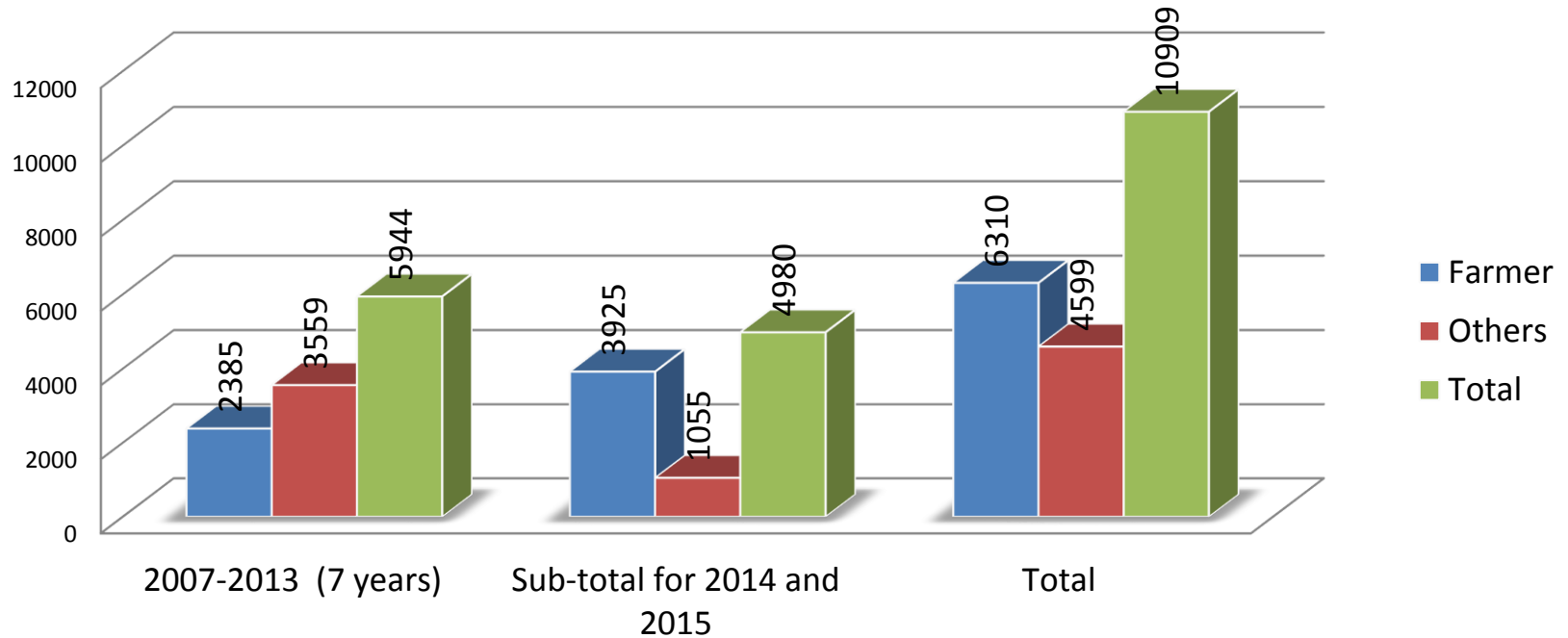
वर्ष 2013-14 की तुलना में 2014-15 में 23% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में 13% की और अधिक वृद्धि हुई है ।

संयुक्त देयता समूह गठन (भूमिहीन किसान)



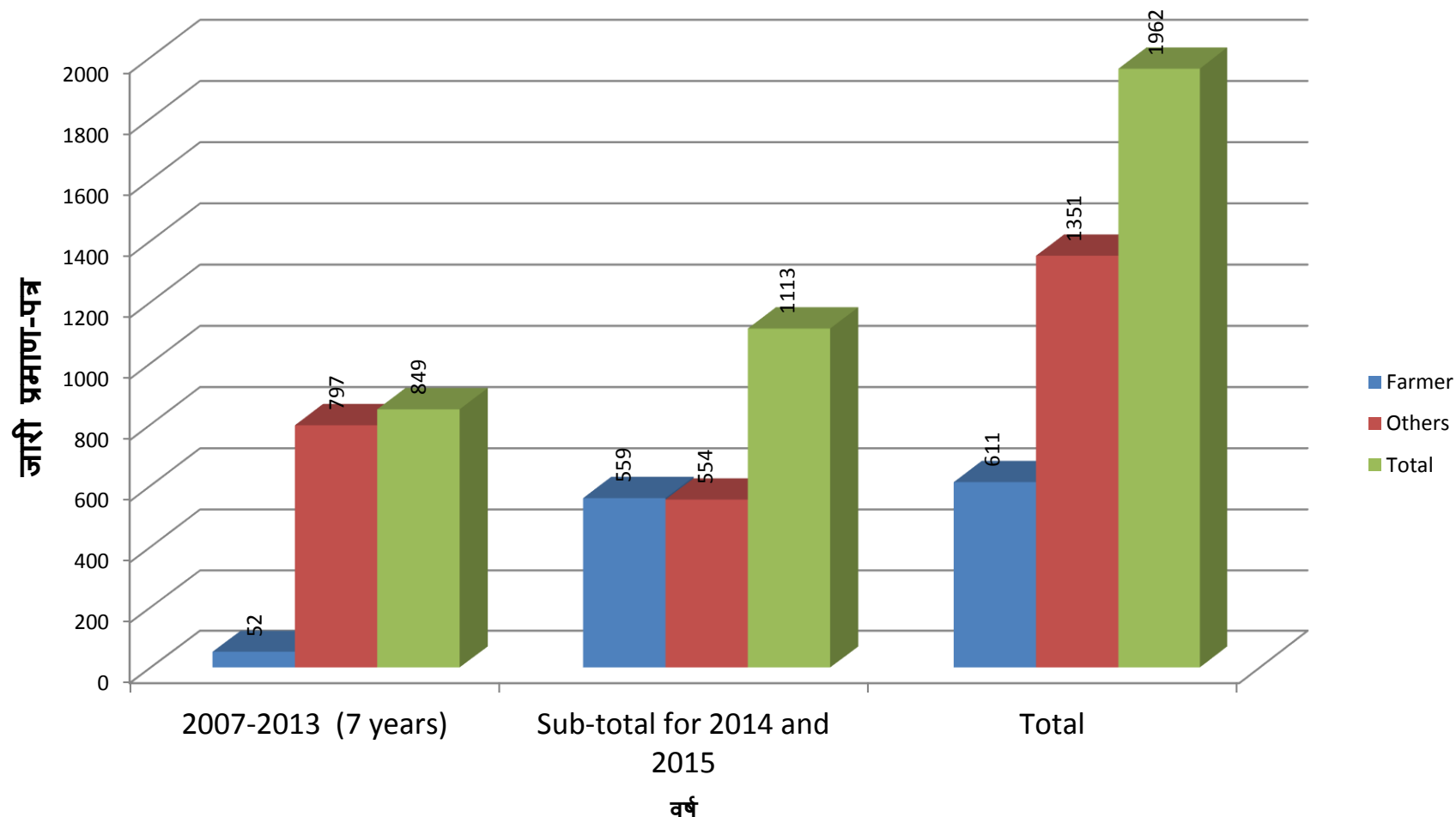
मार्च, 2014 तक 6.72 लाख रुपए की संचयी उपलब्धि की तुलना में, नवंबर 2015 से अप्रैल 2014 के बीच 7.28 लाख संयुक्त देयता समूह का गठन किया गया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पात्रता प्राप्त आवेदन



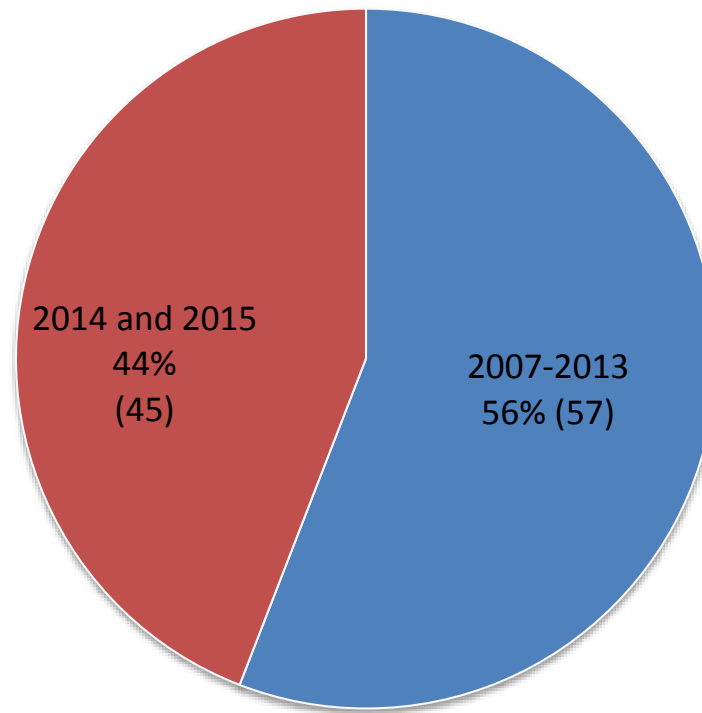
वर्तमान मोदी सरकार में पादप किस्म संरक्षा (पीवीपी) हकदारी के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या यूपीए सरकार के 7 सालों की तुलना में लगभग दुगुनी हुई है ।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण जारी किये गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

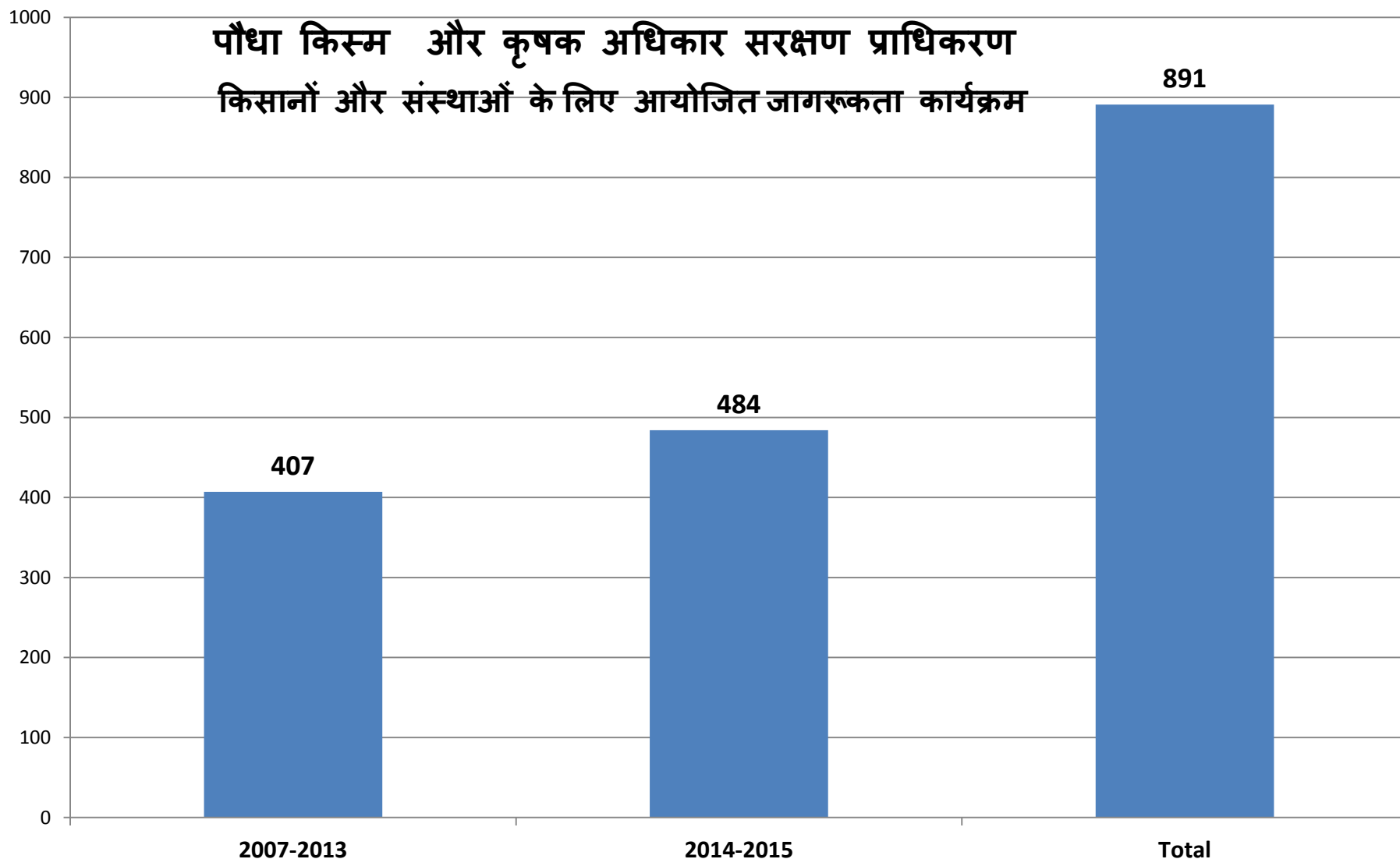


मोदी सरकार में पीवीपी-हकदारी के लिए जारी किये गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या यूपीए सरकार से लगभग 1.5 गुणा अधिक है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पंजीकरण के लिए राजपत्र में अधिसूचित फसल किस्मों



पिछली सरकार के 7 वर्षों की अवधि के दौरान फसल किस्मों (पीवीपी-हकदारी) के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 57 फसल किस्मों हैं, जबकि वर्तमान सरकार के केवल दो वर्षों में ही 45 नई किस्मों अधिसूचित की गईं।



पिछली सरकार की 7 वर्ष की अवधि में पौध किस्मों की संरक्षा और किसान अधिकार प्राधिकरण द्वारा चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम केवल 407 थे, जबकि वर्तमान मोदी सरकार में 484 कार्यक्रम आयोजित किए गए।